राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 37 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शनिवार ,07 अगस्त 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

अमेरिका में विमान हादसा, छह की मौत

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के अलास्का में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से छह लोगों की मौत हो गयी है। अलास्का पलिक मीडिया न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डी हैविलैंड बीवर विमान गुरुवार को लगभग 19:20 बजे पर तटरक्षक बल को एक आपातकालीन संकेत भेजने के बाद केचिकन शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। न्यूज चैनल के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल के दो तैराक मौके पर पहुंचे,लेकिन किसी को जीवित नहीं पाया। अभी तक हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया है।

तमिलनाडु में केन्द्रीय कारागारों पर छापा

चेन्नई, (एजेंसी) । तमिलनाडु पुलिस की विशेष टीमों ने जेलों में कैदियों के पास प्रतिबंधित पदार्थ अथवा सेलफोन का पता लगाने के लिए राज्य के सभी नौ केन्द्रीय कारागार में शुक्रवार की सुबह छापे मारे। माधवरम के सहायक आयुत सुंदरवधानम के नेतृत्व में 100 सदस्यीय टीम ने यहां के पुझल जेल में छापेमारी की। इसी तरह कुड्डालोर, सलेम, मदुरै और पलायमकोट्टई की केंद्रीय जेलों में भी एक साथ छापेमारी की गई।

पुष्कर सरोवर में एक महिला का शव मिला

अजमेर, (एजेंसी)। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव तैरता मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्कर सरोवर के झूलेलाल घाट पर महिला का शव तैरता दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नगरपालिका की सहायता से शव को बाहर निकाल कर पुष्कर के अस्पताल भिजवाया।

भाजपा सांसद प्रसाद का राजनीति से संन्यास

बैंगलुरु, (एजेंसी)। कर्नाटक से भाजपा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन पर चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। श्री प्रसाद ने मैसूरु में कहा, कि मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। मैं इस पर कायम रहूंगा। उन्होंने कहा वह 50 साल तक राजनेता रहे और आने वाले दिनों में वह एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। श्री प्रसाद एक दलित व विशेष रूप से मैसूर में राज्य की राजनीति में एक अत्यधिक प्रभावशाली नेता रहे हैं। वह नंजानगुड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्नाटक विधान सभा के सदस्य और चामराजनगर से छह बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने पहले जद-यू और कांग्रेस सहित कईदलों के साथ काम किया है।

मरमत कार्य के कारण श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर वाहनों के आवाजाही बंद

श्रीनगर, (एजेंसी)। केंद्रशासित प्रदेश जमू-कश्मीर का श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को साप्ताहिक रख-रखाव एवं मरमत कार्य के कारण शुक्रवार को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया। एक

यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से जोड़ने वाले श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर और लेह से आने वालों वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जमू-कश्मीर प्रदेश ने घोषणा की है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सड़क के साप्ताहिक रख-रखाव की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर खासकर जोजिला दर्रे पर भी यातायात की आवाजाही हर शुक्रवार को बंद रहेगी। यातायात अधिकारी ने कहा कि राजमार्ग को शनिवार को राजमार्ग की स्थिति और मौसम में

एमएसपी नीति का कृषि अधिनियम से कोई लेना-देना नहीं : नरेन्द्र सिंह तोमर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए किसानों से चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उल्लेखनीय है कि इन कानूनों के विरोध में किसान संगठन संसद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर किसान संसद लगा रहे हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में तोमर ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए सरकार ने सक्रिय रूप से और लगातार किसान संघों के साथ काम किया और मुद्दों को हल करने के लिए किसान संघों से 11 दौर की बातचीत की। इसके बावजूद किसान संघ कभी कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को हल करने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के साथ चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। तोमर ने कहा कि किसानों से पामर्श के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियों और कार्य बलों का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि शंकरलाल गुरु की अध्यक्षता में वर्ष 2000 में विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, वर्ष 2001 में अंतर मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया था जबकि 2010 में कृषि विपणन के 10 प्रभारी राज्य मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था।

गौरतलब है कि संसद के वर्तमान मानसून सत्र में भी अन्य मुद्दों के साथ कृषि कानूनों का मुद्दा छाया है और विपक्षी दल इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तोमर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति का केंद्रीय कृषि कानूनों से कोई लेना-देना नहीं है और किसान अपनी उपज अपने फायदे के अनुसार कहीं भी बेचने को स्वतंत्र हैं। दरअसल, माकपा के सदस्य इलामारम करीम ने सरकार से जानना चाहा था कि केंद्रीय कृषि कानूनों के लागू हो जाने के बाद इसकी खरीदी में उद्योग जगत के एकाधिकार होने की सूरत में किसानों के लिए एमएसपी कैसे सुनिश्चित होगा। जवाब में तोमर ने कहा, एमएसपी नीति का कृषि अधिनियम से कोई लेना-देना नहीं है। किसान अपनी उपज सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी या कृषि उत्पाद मंडी समिति (एपीएमसी) मंडियों में या संविदा खेती के माध्यम से या खुली मंडी में, उनके लिए जो भी फायदेमंद हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दोनों फसल मौसमों में उचित आवश्यक गुणवत्ता (एफएक्यू) की 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। उन्होंने कहा, सरकार अपनी विभिन्न हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य भी प्रदान करती है। एमएसपी पर खरीद, केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत की जा रही है। इसके अलावा समग्र बाजार भी एमएसपी और सरकार के खरीद कार्यों की घोषणा को लेकर प्रतिक्रिया देता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अधिसूचित फसलों के बिक्री मूल्य में वृद्धि होती है। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद वर्ष 2014-15 से एमएसपी की खरीद बढ़ी है। उन्होंने कहा, वर्ष 2014-15 में तिलहन और कोपरा की खरीद 12,097.84 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1,100, 244.89 मीट्रिक टन हो गई है। इसके अलावा वर्ष 2014 -15 में दलहन की खरीद भी 364,171 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 2,191,851.69 मीट्रिक टन हो गई है।

जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता, किसानों के प्रदर्शन में हुए शामिल

नई दिल्ली । विपक्ष ने पेगासस जासूसी प्रकरण, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग को जारी रखने का फैसला लिया है। इस क्रम में शुक्रवार को राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता बस से जंतर मंतर पहुंचे और किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर नारेबाजी की।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, आज सभी विपक्षी पार्टियों ने काले कानूनों को हटाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। हम संसद में पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहां पर वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर हिन्दुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं।

आज सुबह बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने जंतर मंतर पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की भी बात कही थी। ये सभी नेता किसानों के समर्थन में संसद से जंतर मंतर तक पैदल जाने का फैसला लिया था। बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे के कार्यालय में यह बैठक हुई।

बैठक में राहुल गांधी के अलावा रायसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा एवं जयराम रमेश, द्रमुक के टीआर बालू, शिवसेना के संजय राउत और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए।उल्लेखनीय है कि संसद सत्र के मद्देनजर किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर पिछले कुछ दिनों से सांकेतिक 'संसद' का आयोजन किए हुए हैं। किसान संगठनों की मांग तीनों कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की है।

राहुल की ब्रेकफास्ट मीटिंग
गायब आम आदमी पार्टी समे
14 दलों ने इस बैठक में हिस्
लिया। सदन में विपक्ष की मांग
न मानने का आरोप सरकार
लगाया गया है। गुरुवार को खड़
ने सरकार पर आरोप लगाया
और कहा था कि मुद्दों को सरक
नहीं सुलझा रही है और केव
विधेयकों को पारित करवा रही है
उन्होंने कहा कि पेगासस मामले
विपक्ष चर्चा को तैयार है। उन्होंने कह
अभी चर्चा करें हम तैयार हैं।

सूत्रों के अनुसार, विपक्षी नेता
की बैठक में यह भी तय किया ग
कि पेगासस जासूसी मामला अ
महंगाई के मुद्दे पर सरकार को आ
भी घेरा जाएगा। पेगासस और कु
अन्य मुद्दों को लेकर, संसद
मानसून सत्र की शुरुआत से ही दो
सदनों में गतिरोध जारी है। संसदी
कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष
मांग को खारिज करते हुए ग
शुक्रवार को लोकसभा में कहा था वि
यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

भारत-चीन ने गोगरा क्षेत्र से सैनिकों को पीछे हटाय

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गोगरा पेट्रोलिंग प्वाइंट-17-ए से भारत और चीन की सेना पीछे हट गई है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की दिशा में हाल में। दोनों देशों के बीच 12वें दौर की सैन्य स्तर की बातचीत में इस पर सहमित बनी थी। भारतीय सेना की तरफ से शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी गई। दोनों पक्षों द्वारा निर्मित सभी अस्थायी ढांचों, अन्य अवसंरचनाओं को

नष्ट कर दिया गया है और परस्पर तरीके से सत्यापित किया गया है। भारतीय सेना ने कहा कि भारत और चीन, दोनों देशों ने वार्ता को आगे बढ़ाने और पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शेष मुद्दों का समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारतीय थल सेना, भारत तिबत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के साथ राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने और पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि पिछली बैठक में चीन ने पैंगोंग-त्सो इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में विवाद होने से इनकार किया था लेकिन भारत और चीन के विदेश

मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बा
सैन्य कमांडर्स की मीटिंग पर सहम
बनी थी।

शनिवार हुई बैठक के बाद गोग
पेट्रोलिंग प्वाइंट-17ए से दोनों दे
के जवान पीछे हटे हैं। एलएसी विव
के निपटारे के लिए अब त
कूटनीतिक और सैन्य स्तर व
लगातार वार्ताएं हुई हैं। कुछ जगहों
दोनों देशों की सैनिकों की वापसी
भारत और चीन के बीच हुई अ
जवान पुराने ठिकाने पर चले ग
लेकिन, हॉट स्प्रिंग और गोगरा
अभी तक सहमति नहीं बन पाई थ

पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया

नई दिल्ली । खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अब बदल गया है. केंद्र सरकार ने आज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है. इस पुरस्कार को तीन बार ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य मेजर ध्यान चंद के नाम पर रखा गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें देश के कई नागरिकों से खेल रत्न सम्मान को मेजर ध्यान चंद के नाम पर करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे थे. पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल के सबसे बड़े पुरस्कार को अब मेजर ध्यान चंद खेल रत्न के नाम से जाना जाएगा.

मोदी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब भारतीय टीम पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रही है. इस उपलब्धि पर देश भर में जश्न का माहौल है. पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि 'ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रयासों से हम सभी अभिभूत हैं. विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे-बेटियों ने जो इच्छाशक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है.

देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए. लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है.'

मेजर ध्यान चंद का जन्मदिन है 'खेल दिवस'- ध्यान चंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे जिनकी गिनती विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में होती है. वह 1928 में एम्सटर्डम ओलंपिक, 1932 में लॉस एंजेल्स ओलंपिक और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे. उनकी जन्मतिथि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है. भारतीय ओलम्पिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था. खेल रत्न की शुरुआत 1991-92 से हुई थी और यह पहले किसी खिलाड़ी को एक वर्ष में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता था.

2014 में पुरस्कार चयन समिति के सुझावों के आधार पर खेल मंत्रालय ने 2015 में चार वर्ष के प्रदर्शनों को आधार बनाया. अब तक इस पुरस्कार से 38 खिलाड़ी सम्मानित हो चुके हैं और 1991-92 में सबसे पहले यह पुरस्कार शतरंज के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था. यह पुरस्कार 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में दिया गया था.

कांग्रेस पर नहीं रही अब दीदी की ममता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष सड़क से संसद तक सरकार से लड़ाई के मूड में है। मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार राहुल गांधी विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं और ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। मगर हर बार कोई न कोई विपक्षी दल गायब ही रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब शुक्रवार को जंतर-मंतर पर राहुल गांधी संग विपक्ष के प्रदर्शन से कुछ पार्टियां गायब रहीं। दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेता आज शुक्रवार को दोपहर में जंतर-मंतर पहुंचकर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन किया। जंतर-मंतर पर अन्य पार्टियों के नेताओं संग पहुंचे राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने नारे लगाए और उनके हाथ में सेव फार्मर्स, सेव इंडिया यानी किसान बचाओ, देश बचाओ के पोस्टर दिखे। लेकिन इस दौरान सबसे हैरान करने वाली जो बात थी वह यह कि विपक्षी दलों के इस जुटान में टीएमसी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं दिखा। जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों के जमावड़े से ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आप और मायावती की बसपा अलग रही। इससे पहले राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग में आम आदमी पार्टी और बसपा शामिल नहीं हुई थी। मगर यहां चौंकाने वाली बात है कि इस बार जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों के जुटान से टीएमसी गायब रही। बता दें कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में यह फैसला किया गया। इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा एवं जयराम रमेश, द्रमुक के टीआर बालू, शिवसेना के संजय राउत और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि संसद सत्र के मद्देनजर किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर पिछले कुछ दिनों से सांकेतिक संसद का आयोजन किए हुए हैं। किसान संगठनों की मांग तीनों कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की है। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी नेताओं की बैठक में यह भी तय किया गया कि पेगासस जासूसी मामला और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को आगे भी घेरा जाएगा। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर, संसद के मॉनसून सत्र में शुरू से ही दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से यह सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है। विपक्षी दल इस बात जोर देते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए गत शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

जल्दबाजी में विधेयक पास कराने के आरोपों पर वित्त मंत्री ने विपक्ष को दिखाया आईना, कहा- जरा अपना रिकार्ड भी देख लें

नई दिल्ली । पेगासस जासूसी मामले और नए कृषि कानूनों को लेकर संसद में गतिरोध कायम है। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। हालांकि इस बीच कुछ विधेयक पारित भी हुए हैं। इस पर भी विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना चर्चा कराए जल्दबाजी में विधेयक पास करा रही है। विपक्ष के इन्हीं आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस को अपना रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसा बोल रहा है कि जल्दबाजी में बिल पास कर रहे हैं। साल 2007 में विपक्ष ने कम से कम 11 बिल जल्दबाजी में पास कराए। इसके बाद साल 2011 में संविधान विधेयक को भी जल्दबाजी में पास करा लिया तब यूपीए सत्ता में था। पास कराए हैं। पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी बार-बार कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। फिर भी विपक्ष हमें कह रहा है कि जल्दबाजी में बिल पारित कराए जा रहे हैं। थोड़ा अपना रिकॉर्ड भी निकालकर देखें...

वित्त मंत्री सीतारमण का बयान विपक्ष के उन आरोपों पर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि सरकार आनन फानन में विधेयकों को पारित करा रही है। लोकसभा में कांग्रेस ससंदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को कहा था कि

में एक विधेयक पारित कर र
है। आरएसपी के एन
प्रेमचंद्रन ने भी टैक्स सुध
संशोधन बिल पेश किए जा
का विरोध किया था। यही न
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्राय
ने भी सरकार पर आपाधापी
विधेयकों को पारित कराने व
आरोप लगाया था।

उल्लेखनीय है कि पेगास
जासूसी मामला और नए कृषि कानू
को लेकर विपक्षी सदस्यों ने शुक्रव
को भी संसद में जमकर हंगा
किया। हंगामे के कारण शुक्रवार व
लोकसभा की कार्यवाही एक बार
स्थगन के बाद दोपहर करीब 1
बजकर 25 मिनट पर दिन भर व
लिये स्थगित कर दी गई। हालांवि
विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बी
ही लोकसभा ने कराधान वि
(संशोधन) विधेयक 2021 अ
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन
विधेयक 2021 को मंजूरी दे द
हंगामे के बीच ही केंद्रीय मंत्रियों

संक्षिप्त समाचार

अफगानिस्तान में लौटा कट्टरता का दौर, तालिबानियों ने की सूचना मीडिया केंद्र के निदेशक की हत्या

काबुल, अफगानिस्तान। अफगान गृह मंत्रालय के अनुसार अफगानिस्तान के सरकारी सूचना मीडिया केंद्र के निदेशक की बंदूकधारियों ने गोली मार कर हत्या की कर दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी सूचना मीडिया केंद्र के निदेशक की हत्या की जिम्मेदारी ली। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि समूहों के लड़ाकों ने दावा खान मेनपाल को मार डाला था, जो स्थानीय और विदेशी मीडिया के लिए सरकार के प्रेस अभियान चलाते थे। मुजाहिद ने बाद में जारी एक बयान में कहा कि मेनपाल 'मुजाहिदीन के एक विशेष हमले में मारा गया था' और उसे 'उसके कामों की सजा दी गई थी। मुजाहिद ने और अधिक जानकारी नहीं दी। इसे भी पढ़ें- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत लगभग 12,500 लड़कियों को मिल रहा है लाभ- सरकार पत्रकारों के लिए अफगानिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। नागरिकों के खिलाफ हाल के कई हमलों का दावा इस्लामिक स्टेट द्वारा किया गया है, हालांकि इन हमलो के लिए सरकार अक्सर तालिबान को जिम्मेदार ठहराती है।

आतंकवादी समूह हिज्बुल्लाह ने इजरायली ठिकानों के निकट रॉकेट दागे

बेरूत। लेबनान के आतंकवादी समूह हिज्बुल्ला ने कहा है कि उसने आज दिन में दक्षिणी लेबनान में हुए हवाई हमलों के जवाब में लेबनानी सीमा के निकट इजराइली ठिकानों के निकट रॉकेट दागे हैं। हिज्बुल्ला ने एक बयान में कहा कि उसने शेबा फार्म्स इलाके में इजराइली ठिकानों के निकट खुले मैदान में दर्जनों रॉकेट बरसाए। हालांकि इसके अतिरिक्त उसने कोई जानकारी नहीं दी।

वेनेजुएला में महंगाई सातवें आसमान पर, पांच लीटर पानी की कीमत 1.84 अमेरिकी डॉलर हुई

कराकस (वेनेजुएला)। वेनेजुएला सातवें आसमान पर पहुंची महंगाई दर से जूझ रहा है और इसकी वजह से उसकी मुद्रा बोलीवर की कीमत में भारी गिरावट आयी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने कहा कि उसकी नयी मुद्रा व्यवस्था के तहत वर्तमान में 10 लाख बोलीवर की कीमत एक बोलीवर हो जाएगी। इसका करण तेजी से बढ़ती महंगाई दर है। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि बोलीवर में बदलाव एक अक्टूबर से प्रभावी होगा। नयी व्यवस्था में 100 बोलीवर सबसे बड़ा नोट होगा और उसकी कीमत वर्तमान 10 करोड़ बोलीवर के बराबर होगी। यह लगातार छठा साल है, जब वेनेजुएला में मंदी की स्थिति बनी हुई है। खाद्य वस्तुएं महंगी होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे गरीबी में फंसते जा रहे हैं। फिलहाल 10 लाख बोलीवर सबसे बडा नोट है, लेकिन यह दुर्लभ है। यहां पांच लीटर पानी की बोतल की कीमत बृहस्पतिवार को 74 लाख बोलीवर या 1.84 अमेरिकी डॉलर हो गयी।

अफगानिस्तान के शिबरघन शहर में 40 तालिबान आतंकवादी मारे गए

काबुल। अफगानिस्तान की सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कम से कम 40 तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं और लड़ाकू विमानों द्वारा समर्थित सुरक्षा अभियान शुक्रवार को अफगानिस्तान के जवाजान प्रांत की राजधानी शिबरघन शहर में जारी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बयान के हवाले से कहा कि लड़ाकू विमानों द्वारा समर्थित सुरक्षा बलों ने आज शिबरघन शहर पर तालिबान के हमले को नाकाम करने के लिए एक जवाबी हमले में 40 विद्रोहियों को मार गिराया और 15 अन्य को पकड़ लिया। बयान में कहा गया है कि तालिबान विद्रोही शिबरघन शहर में घरों में घुस गए और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी बलों को जोड़ने से शहर को साफ होने तक विद्रोहियों को निशाना बनाना जारी रहेगा। शिबरघन के अधिकारियों और निवासियों के अनुसार तालिबान आतंकवादी शुक्रवार सुबह शहर में घुसे और मुठभेड़ जारी है। तालिबान संगठन ने गतिविधियों को तेज कर दिया है और मई की शुरूआत से लगभग 200 जिलों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें कुछ जवज्जन में भी शामिल हैं। समूह हेरात, लश्कर गाह, शिबरघन और मैमाना सहित बड़े शहरों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है।

फ्रांस की शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य पास के व्यापक उपयोग को मंजूरी दी

पेरिस। फ्रांस के सर्वोच्च संवैधानिक निकाय ने स्वास्थ्य पास के उपयोग को सार्वजनिक स्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला में विस्तारित करने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोविड -19 टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, संवैधानिक परिषद ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य पास के उपाय संविधान का पालन करते हैं। अधिक संक्रामक कोविड -19 रूपों के प्रसार को रोकने के लिए, सरकार ने जुलाई में प्रस्ताव दिया कि कैफे, रेस्तरां, जिम, शॉपिंग सेंटर और यहां तक कि अस्पतालों (आपात स्थिति को छोड़कर) में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को एक प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो साबित कर सके कि वे पूरी तरह वैक्सिनेटिड है, उन्होंने नकारात्मक परीक्षण किया है, या हाल ही में कोरोनावायरस से रिकवर हुए है। फ्रांस में, सिनेमाघरों और संग्रहालयों जैसे सांस्कृतिक और अवकाश स्थलों में 50 से अधिक लोगों की सभा के लिए 21 जुलाई से स्वास्थ्य पास अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच, अदालत ने कोविड -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 10-दिवसीय क्वारंटीन लगाने की सरकार की इच्छा को खारिज कर दिया।

अफगानिस्तान को लेकर रूस ने बुलाई बैठक, चीन, अमेरिका और पाक को बुलावा, भारत से बनाई दूरी

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के बीच रूस ने एक अहम बैठक बुलाई है। सबसे खास बात तो यह है कि रूस की इस बैठक में पाकिस्तान, चीन तथा अमेरिका के शामिल होने की संभावना है। लेकिन भारत को इसका निमंत्रण नहीं भेजा गया है। कतर में आयोजित होने वाली इस बैठक का नाम 'विस्तारित ट्रोइका' होगा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान को लेकर रूस ने कोई बैठक की है और उसमें भारत को निमंत्रण नहीं दिया है। इससे पहले भी अफगानिस्तान पर बैठक में रूस ने भारत को नहीं बुलाया था। उस समय भी भारत-रूस के संबंधों को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। यह बैठक 11 अगस्त को कतर में होनी है।

इससे पहले इसी प्रारूप के तहत एक बैठक 18 मार्च और 30 अप्रैल को हुई थी। अफगानिस्तान में शांति कायम करने और राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया की शर्तें तय करने के लिए रूस मास्को फॉर्मेट भी आयोजित करा रहा है। रूस लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमले में हिंसा रोकने तथा अफगान शांति प्रक्रिया पर जोर देने के लिए युद्ध ग्रस्त देश में सभी प्रमुख हितधारकों तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए हैं। 'विस्तारित ट्रोइका' की बैठक का आमंत्रण नहीं दिए जाने के बाबत सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर नयी दिल्ली और मास्को के बीच नियमित रूप से बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक विशेष रणनीतिक साझेदारी से बंधे हैं। हम अफगानिस्तान पर रूस के साथ नियमित रूप से चर्चा करते हैं।

भारत-रूस संबंध

रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव ने पिछले महीने ताशकंद में कहा कि उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ काम करता रहेगा जो अफगानिस्तान में स्थिति पर असर डाल सकते हैं। इन टिप्पणियों के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भारत को आगामी ''विस्तारित ट्रोइका' बैठक में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद माना जा रहा था कि अफगानिस्तान को लेकर रूस के इस बैठक के में भारत को निमंत्रण मिल सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या भारत और रूस के संबंध ठीक नहीं है? क्योंकि माना जाता है कि आजादी के बाद से ही भारत और रूस के संबंध बेहतर रहे है। हालांकि फिलहाल दोनों देशों के संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है। इसी साल भारत-रूस शिखर सम्मेलन प्रस्तावित था जिसे रद्द कर गया। बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से इसे रद्द किया गया है। इस बैठक में खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होने वाले थे। वर्ष 2000 के बाद यह पहला मौका है जब भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन को टाला गया है। पिछले 20 सालों से यह लगातार आयोजित होता रहा है।

भारत की चिंता

भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि चीन और रूस के संबंध मजबूत हुए है। पिछले साल अक्टूबर में व्लादिमीर पुतिन ने वल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब की 17 वीं वर्षगांठ पर आयोजित बैठक में चीन, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का नाम लिया था लेकिन भारत के लिए कुछ नहीं कहा था। रूस और चीन दोनों देशों ने अपने रिश्तो को मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने की रणनीति लगातार बनाई जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो भारत और रूस के बीच कई बड़े रक्षा सौदे अधर में लटके हुए है। भारत पर यह भी आरोप लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में स-400 की खरीद के बाद वह रूस से नया रक्षा खरीद समझौता करने से बच रहा है। रूस की सहमति से ही देश में राइफल का कारखाना तैयार हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच कामोव केए-226 मैरिटाइम हेलीकॉप्टर की कीमत का मामला फंसा हुआ है। साथ ही साथ एके-203 के उत्पादन को लेकर अभी तक औपचारिक सहमति नहीं बन पाई है।

इस बीच, भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुन्दजे ने अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा करने के लिए छह अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक कराने के फैसले को सकारात्मक कदम बताया।संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने एलान किया कि भारत की अध्यक्षता के तहत शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा की जाएगी। मामुन्दजे ने ट्वीट किया, ''अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बुलाना एक सकारात्मक कदम है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों की हिंसा और अत्याचारों के कारण अफगानिस्तान में हो रही

त्रासदी को रोकने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। यूएनएससी अध्यक्ष के तौर पर अग्रणी भूमिका के लिए शुक्रिया भारत।'' यूएनएससी की बैठक कराने का फैसला तब आया है जब दो दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने तालिबान की हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बुलाने पर अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात की। भारत अगस्त माह के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है।अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता में भारत प्रमुख पक्षकार है। उसने युद्धग्रस्त देश में सहायता और पुनर्निर्माण गतिविधियों में करीब तीन अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है।भारत अफगानिस्तान के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शांति एवं सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है।

दक्षिण कोरिया, अमेरिका, प्योंगयांग की सहभागिता की कोशिशों पर सहमत

सियोल (एजेंसी)।

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग यूई-योंग और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को एक फोन कॉल के दौरान प्योंगयांग के साथ बातचीत करने और कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति कायम रखने के लिए निरंतर कोशिश करने पर सहमति जताई।

योनहाप समाचार एजेंसी ने सियोल में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के हवाले से कहा, मंत्री और सचिव इस बात पर सहमत हुए कि दक्षिण और अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप पर पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण और स्थायी शांति की स्थापना के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति के लिए समन्वित राजनयिक प्रयास करना जारी रखेंगे। इसमें कहा गया है, विशेष रूप से, दोनों देशों ने मानवीय सहयोग सहित उत्तर के साथ सहयोग के तरीकों पर ठोस परामर्श किया और उत्तर के साथ जुड़ाव के प्रयासों को जारी रखने पर सहमत हुए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि ब्लिंकन ने अंतर-कोरियाई सुलह के लिए अमेरिकी समर्थन दोहराया। प्राइस ने कहा, सचिव और विदेश मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण और स्थायी शांति की स्थापना के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सचिव ने इंटर-कोरियाई वार्ता और जुड़ाव के लिए अमेरिकी समर्थन की पुष्टि की।

पाकिस्तान में लोगों ने हिंदू मंदिर पर किया हमला, मूर्तियां भी तोड़ी, इमरान खान ने दिए जांच के आदेश

लाहौर। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीड़ ने हिंदुओं के एक मंदिर पर हमला कर मूर्तियों को खंडित कर दिया और मंदिर के कुछ हिस्से को जला दिया। इस पर, प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्षतिग्रस्त मंदिर का जीर्णोद्धार करने और सभी दोषियों को गिरफ्तार करने का वादा किया। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद ने ''गंभीर चिंता'' प्रकट की और उन्होंने न्यायालय में इस विषय की सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध की है।

पाकिस्तान में क्यों तोड़ा गया हिंदू मंदिर

पुलिस ने बताया कि रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में भीड़ ने बुधवार को हिंदू मंदिर पर हमला किया। यह स्थान लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने बताया गया कि एक मदरसे के

पुस्तकालय को कथित तौर पर अपवित्र करने की घटना के बाद कुछ लोगों के उकसाने पर भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया। पिछले हफ्ते हिंदू समुदाय के आठ साल के एक बच्चे ने इलाके के मदरसे के पुस्तकालय में कथित तौर पर पेशाब कर दिया था, जिसके बाद भोंग में तनाव व्याप्त हो गया। इस इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग दशकों से शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए हैं।

आठ साल के मासूस हिंदू बच्चे पर दर्ज किया गया मामला

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुस्तकालय को कथित तौर पर अपवित्र करने वाले आठ वर्षीय बच्चे के खिलाफ ईशनिंदा का मामला दर्ज कर पिछले हफ्ते उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, उसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। रहीम यार खान के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) असद सरफराज ने बताया, '' हमलावरों ने डंडे, पत्थर और ईंटें उठा रखी थीं। उन्होंने धार्मिक नारे लगाते हुए देवी-देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी।'' उन्होंने बताया कि मंदिर के एक हिस्से को जला भी दिया गया। सरफराज ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हालात काबू में कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया है। उन्होंने कहा, ''रेंजर्स को बुलाया गया और हिंदू मंदिर के इर्द-गिर्द तैनात किया गया।''

डेल्टा से भी खतरनाक होगा कोरोना का अगला वेरिएंट, दर्द और पीड़ा का सामना करेंगे लोग: डॉ एंथनी फाउची

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एंथनी फाउची ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अधिक ''दर्द और पीड़ा'' का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे है। साथ ही उन्होंने उन नागरिकों से टीका लगवाने का अनुरोध किया जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। फाउची ने कहा कि उन्हें अमेरिका में अतिरिक्त लॉकडाउन की उम्मीद नहीं है क्योंकि पिछली सर्दियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पर्याप्त लोगों को टीका लगाया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी ''महामारी को खत्म'' करने के लिए पर्याप्त टीकाकरण नहीं हुआ है।

फाउची ने रविवार को एबीसी के ''दिस वीक'' पर कहा, ''मुझे विश्वास है, अतिरिक्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम भविष्य में कुछ दर्द और पीड़ा देख रहे हैं क्योंकि हम मामलों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, यही कारण है कि हम बार-बार कहते रहते हैं कि इसका समाधान टीकाकरण है।'' जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के 30 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक नए मामले 16 जुलाई को 30,887 से बढ़कर 30 जुलाई को 77,827 हो गये और इसी अवधि में मृतकों की संख्या भी बढ़ी है जो 16 जुलाई को 253 से बढ़कर 30 जुलाई को 358 हो गई।

रोग नियंत्रण और रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) के आंकड़े के अनुसार, वर्तमान में 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 58 प्रतिशत अमेरिकियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। सीडीसी ने टीकाकरण के बाजवूद देशभर के स्कूलों में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और आगंतुकों के लिए मास्क पहनने की भी सिफारिश की है।

यूरोपीय संघ के यात्रा मानचित्र में अधिक लाल, नारंगी जोन दिखाई दिए

ब्रसेल्स (एजेंसी)।

यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल (ईसीडीसी) ने कहा है कि महाद्वीप में कोविड -19 महामारी के पुनरुत्थान को सीमाओं के खुलने और यात्रा प्रतिबंधों में ढील से जोड़ा जा सकता है। ईसीडीसी द्वारा गुरुवार को जारी किया गया यात्रा कार्ड बहुत उत्साहजनक नहीं था। यूरोप अब एक हफ्ते पहले की तुलना में लाल जोन में है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, महाद्वीप का दक्षिण, जहां कई पर्यटक मिलते हैं, महामारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र प्रतीत होता है। दक्षिण में, फ्रांस, ग्रीस और इटली ने अपने क्षेत्रों में नए नारंगी और लाल क्षेत्रों में बढ़ते देखा है। इतालवी प्रायद्वीप में, सिसिली और सार्डिनिया द्वीपों को छोड़कर सब नारंगी जोन थे, लेकिन अब टस्कनी और मार्चे भी लाल जोन में आ गए हैं। इस हफ्ते, उत्तर भी धीरे धीरे लाल जोन आ रहा है, जैसा कि एस्टोनिया और आइसलैंड के मामलों में हुआ। फिनलैंड में, हेलसिंकी उन कई क्षेत्रों में से एक है जो लाल जोन में हैं। फिनिश नेशनल ब्रॉडकास्टर येल के अनुसार, डेल्टा वेरिएंट के त्वरित प्रसार के साथ, राजधानी हेलसिंकी सहित तीन सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन बुधवार से तेजी से फैलने वाली महामारी के चरण में प्रवेश करने के लिए किया गया है। नॉर्डिक देश में लागू मौजूदा महामारी वर्गीकरण मानदंड के अनुसार यह सबसे गंभीर चरण है। डब्ल्यूएचओ यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हैंस क्लूज ने पिछले महीने कहा था कि महाद्वीप में डेल्टा वेरिएंट के प्रसार से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जो पूरे महाद्वीप में सबसे प्रमुख तनाव बन गया है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) और ईसीडीसी ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी कर इस बात पर जोर दिया कि डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए पूर्ण कोविड 19 टीकाकरण महत्वपूर्ण है।

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल पूरे होने पर पाकिस्तान ने भारत की आलोचना की

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा समेत पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने दो साल पहले आज के दिन जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा रद्द करने के भारत के फैसले की बृहस्पतिवार को आलोचना की और कश्मीरी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारतीय संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को पांच अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों--जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख--में बांट दिया था। भारत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान ने दिल्ली के साथ अपने रिश्तों को लेकर कदम पीछे खींच लिए थे और व्यापारिक संबंध स्थगित कर दिए थे। भारत ने कहा है कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री खान ने कहा कि पांच अगस्त 2019 की भारत की एकतरफा एवं अवैध कार्रवाई को आज दो साल हो गए हैं।

पाकिस्तान इस मौके पर 'यौम-ए-इस्तेहसाल' मना रहा है। उन्होंने भारत पर क्षेत्र की जनसांख्यिकी में बदलाव की कोशिश का आरोप लगाते हुए दावा किया ,÷इन दो साल में दुनिया अप्रत्याशित दमन का गवाह बनी है।÷ खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए हर मंच पर अपनी आवाज उठाता रहेगा। फौज के एक बयान के मुताबिक, जनरल बाजवा ने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर के लोगों को सैन्य घेराबंदी में रख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक कश्मीर विवाद का हल निकाला जाए। इस बीच, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कश्मीर की स्थिति के बारे में भारतीय विदेश मंत्री के बयान को निराधार बताकर खारिज कर दिया।

विदेश कार्यालय ने न्यू जम्मू कश्मीर पर भारतीय मंत्री के ट्वीट के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में सबसे लंबे समय विचाराधीन मुद्दों में से एक है। विदेश कार्यालय ने पांच अगस्त, 2019 को भारत की एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए यहां भारतीय राजदूत को भी तलब किया और सख्त आपत्तिपत्र जारी किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कश्मीरियों के समर्थन में आयोजित एक रैली में हिस्सा लिया और बाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत आग से खेल रहा है और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को तबाह कर रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान भारत के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि नई दिल्ली पांच अगस्त 2019 के अपने फैसले को रद्द नहीं करती।

रैली में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना मंत्री फवाद चौधरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री शिबली फराज़, रेल मंत्री आज़म स्वाति और सरकार के अधिकारी व समाज के अन्य तबकों के कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए, कुरैशी ने कहा कि पूरा पाकिस्तानी राष्ट्र और कश्मीरी लोग भारत सरकार के पांच अगस्त 2019 के अवैध और एकतरफा कदमों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा, ÷हम कश्मीरी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे।÷ जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के भारत के कदम की निंदा करने के लिए विरोध रैलियां, एकजुटता वॉक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

इस साल एक लाख ग्रीन कार्ड के बर्बाद होने का खतरा, भारतीय आईटी पेशेवरों में नाराजगी

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

रोजगार आधारित करीब एक लाख ग्रीन कार्ड्स के दो महीने के भीतर बर्बाद होने का खतरा है जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों में नाराजगी है जिनका वैध स्थायी निवास का इंतजार अब दशकों तक के लिए बढ़ गया है। आधिकारिक तौर पर स्थायी निवास कार्ड के तौर पर जाने जाना वाला ग्रीन कार्ड आप्रवासियों को साक्ष्य के तौर पर जारी एक दस्तावेज है कि धारक को अमेरिका में स्थायी रूप से निवास करने की सुविधा दी गई है। भारतीय पेशेवर संदीप पवार ने बताया कि इस साल आप्रवासियों के लिए रोजगार आधारित कोटा 2,61,500 है जो 1,40,000 के सामान्य तौर पर कोटा से काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से, कानून के तहत, अगर ये वीजा 30 सितंबर तक जारी नहीं किए जाते, तो ये हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं।'

उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा या यूएससीआईएस द्वारा वीजा प्रक्रिया की मौजूदा गति दिखाती है कि वे 1,00,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बेकार कर देंगे। इस तथ्य की वीजा उपयोग निर्धारित करने वाले विदेश मंत्रालय के प्रभारी ने हाल में पुष्टि भी की थी। पवार ने खेद जताया कि अगर यूएससीआईएस या बाइडन प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता तो इस साल उपलब्ध अतिरिक्त 1,00,000 ग्रीन कार्ड बर्बाद हो जाएंगे। इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों पर व्हाइट हाउस ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच, अमेरिका में रह रहे 125 भारतीयों एवं चीनी नागरिकों ने प्रशासन द्वारा ग्रीन कार्ड बर्बाद होने से रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया है।

पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी-मयूर विहार मेट्रो सेवा शुरू

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी-मयूर विहार सेक्शन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा. इसके शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. क्योंकि मेट्रो की एनसीआर की सभी लाइनें आपस मे जुड़ जाएंगी. इससे एनसीआर के किसी भी शहर जाने के लिए यात्रियों को बार-बार मेट्रो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बता दें कि पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा कॉरिडोर है. अब तक इस कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाएं न होने की वजह से यात्रियों को पिंक लाइन पर दो अलग-अलग छोर पर मेट्रो सेवा उपलब्ध थी. कोरोना के समय में इस सेवा की शुरुआत को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. गौरतलब है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 10:15 बजे इस सेक्शन पर मेट्रो सेवा की शुरुआत करेंगे. वहीं तीन बजे से यात्री इस सेक्शन पर यात्रा कर सकेंगे.

आपस में जुड़ेंगी ये लाइनें- नई सेवा शुरू होने के बाद एनसीआर को जाने वाली मेट्रो की रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन और वायलेट लाइन इस कारिडोर के शुरू होने से पिंक लाइन से जुड जाएंगी. अब अगर किसी को नोएडा, गाजियाबाद समेत पूर्वी दिल्ली से फरीदाबाद या गुरुग्राम जाना होगा तो उनको ब्लू, रेड, येलो होते हुए वॉलेट लाइन के बीच चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा. पिंक लाइन पर इंटरचेंज की सुविधा होने से यात्री अपनी मंजिले की ओर जाने वाली मेट्रों में सवारी कर सकेंगे. बताया जा रहा है कि पिकं लाइन की कुल लंबाई 58.6 किलोमीटर है. अभी त्रिलोकपुर और मयूर विहार के बीच मेट्रो सेवाएं नहीं थी. इस वजह से यात्रियों को शिव विहार-त्रिलोकपुरी और मजलिस पार्क-मयूर विहार पॉकेट -1 पर दो अलग-अलग कॉरिडोर पर सफर का मौका मिल रहा था.

त्रिलोकपुरी संजय लेक-मयूर विहार पॉकेट-1 सेक्शन से यात्रियों को लाभ- पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी-संजय लेक और मयूर विहार पॉकेट-1 स्टेशनों के बीच इस मिसिंग लिंक पर 290 मीटर लंबे खंड पर कॉरिडोर बनाया गया है. इसके द्वारा महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सेंटर जैसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय काले खां आईएसबीटी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार आईएसबीटी, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और प्रमुख बाजार जैसे दिल्ली हाट-आईएनए, सरोजनी नगर और लाजपत नगर को सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी. फेज-2 में इस कॉरिडोर को आगे मजलिस पार्क से मौजपुर तक बढ़ाया जाएगा जिससे लगभग 70 कि.मी. लंबा यह कॉरिडोर भारत का सबसे लंबा सिंगल मेट्रो कॉरिडोर बन जाएगा. फेज-2 के पूरा होने के बाद पिंक लाइन देश में मेट्रो का एकमात्र रिंग कॉरिडोर भी बन जाएगी.

डीएमआरसी के मुताबिक इस खंड का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि महामारी के कारण लॉकडाउन लगने और मजदूरों के उपलब्ध ना होने जैसे मुद्दों के कारण काम बार-बार रोका गया. वहीं चलते रहने के बावजूद इस खंड पर सिविल निर्माण कार्य जारी रहा और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हुआ.

इसके साथ ही डीएमआरसी त्रिलोकपुरी वायाडक्ट के नीचे एक इंटरनल रोड भी विकसित कर रही है, जो वसुंधरा रोड और त्रिलोक पुरी रोड को आपस में जोड़ेगा. यह रोड 140 मीटर लंबा होगा. इससे क्षेत्र में भीड़भाड़ कम होने में मदद मिलेगी और यातायात में भी सुधार होगा.

इसमें लगाए गए हैं कंक्रीट के बजाय स्टील गर्डर- काम में तेजी लाने और साइट के पास कास्टिंग यार्ड के लिए जगह उपलब्ध न होने के कारण पारंपरिक कंक्रीट गर्डरों के बजाय स्टील गर्डरों के इस्तेमाल से निर्माण का एक अनूठा तरीका अपनाया गया है. 10 स्पैनों पर कुल 40 गर्डर रखे गए हैं. स्टील गर्डरों को तैयार करके हरियाणा स्थित अंबाला की एक वर्कशॉप से लाया गया. इन गर्डरों की लंबाई 16 से लेकर 38 मीटर तक है. वायाडक्ट की ऊंचाई लगभग 8 से 9.5 मीटर तक है. 200 मीटर व्यास वाला एक घुमावदार स्पैन भी इस खंड का हिस्सा है. इस वजह से एक साल से भी कम के रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण पूरा हो सका.

यह है पिंक लाइन पर मेट्रो ट्रेन संचालन का पूरा प्लान- मयूर विहार पॉकेट-1 से त्रिलोकपुरी-संजय लेक स्टेशनों के बीच वाले खंड की कनेक्टिविटी के बाद पूरी पिंक लाइन (मजलिस पार्क से शिव विहार) पर इस ऑपरेशनल प्लान के तहत ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होंगी.

-मजलिस पार्क से सराय काले खाँ, निजामुद्दीन और शिव विहार से आईपी एक्सटेंशन सेक्शनों पर ट्रेन सेवाएं 5 मिनट 12 सेकेंड की फ्रीक्वेंसी के साथ उपलब्ध होंगी, जिनमें पीक घंटों के दौरान 43 (स्टेंडबाई सहित) ट्रेनें भी शामिल होंगी.

- सराय काले खाँ निजामुद्दीन से आईपी एक्सटेंशन सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं 10 मिनट 24 सेकेंड की फ्रीक्वेंसी के साथ उपलब्ध होंगी जिनमें हर एक आल्टरनेट/दूसरी ट्रेन निजामुद्दीन से आईपी एक्सटेंशन की ओर तथा इसकी विपरीत दिशा में चलेंगी.

- मयूर विहार पॉकेट-1 और त्रिलोकपुरी-संजय लेक स्टेशनों (दूरी लगभग 1.5 कि.मी.) के खंड के बीच ऑटोमेटिड सिग्नलिंग सिस्टम न होने के कारण ट्रेनें 25 कि.मी.प्र.घं. की अस्थायी प्रतिबंधित गति से चलेंगी क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम अभी लगाया जा रहा है.

- इस खंड विशेष पर सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि यह लाइन पहले से ही ऑपरेशनल है, इस सिस्टम के अगले दो माह में लगाए जाने की संभावना है. इसके बाद, इस खंड पर भी ट्रेनें नियमित गति से चलने लगेंगी और गति सीमा का प्रतिबंध हट जाएगा.

अयोध्या में सामाजिक समरता का भी संदेश देगा श्री राम जन्मभूमि मंदिरः विहिप

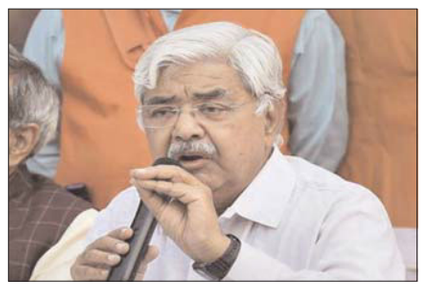

नई दिल्ली । अयोध्या में बन रहा भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश देगा। इसके परिसर में महाकाव्य रामायण के जरिये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन व आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि का भी बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। यह मंदिर 70 एकड़ के परिसर में मुख्य राम मंदिर के नजदीक ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां हर भक्त आसानी से पहुंच सके।

परिसर में अन्य देवी-देवताओं के मंदिरों की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद से अयोध्या में राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि मंदिर की स्थापना की साधु-संतों के साथ ही बड़ी संख्या में रामभक्त भी मांग कर रहे थे। खुद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने उनका यह अनुरोध श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तक पहुंचाया था।

आलोक कुमार ने बताया कि उनके इस आग्रह को ट्रस्ट ने स्वीकृति दे दी है। हालांकि, मंदिर और मूर्ति की रूपरेखा को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है। विहिप शुरू से ही सामाजिक समरसता पर जोर देती रही है। जाति के आधार पर हिंदू समाज को बांटने की लगातार कोशिशों के बीच राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि के मंदिर से सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश जाएगा।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि पूरे देश की यह इच्छा थी कि भगवान राम के साथ महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर हो। उनके बिना श्री राम की कल्पना अधूरी है। उन्होंने ही भगवान राम के चरित्र को जन-जन तक पहुंचाया, ऐसे में उक्त परिसर में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर देखकर भक्तों को सुखद अनुभव होगा।

संक्षिप्त खबर

दिल्ली दंगा: पुलिस ने कोर्ट में कहा- नहीं पता चला जांच का विवरण मीडिया को कैसे मिला

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने एक स्थिति रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जांच में यह पता नहीं चल सका है कि दिल्ली दंगों की तहकीकात का ब्योरा मीडिया को कैसे मिला था. पुलिस ने यह रिपोर्ट आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा की उस याचिका पर दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले ही आरोप पत्र की सामग्री को लीक कर दिया गया था. न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह सीलबंद लिफाफे में मिली दिल्ली पुलिस की पृथक जांच रिपोर्ट पढ़ेंगी और तन्हा की याचिका को सुनवाई के लिए 11 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील रजत नायर ने अदालत को सूचित किया कि मामले में स्थिति रिपोर्ट भी दायर कर दी गई है. स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के आदेश के तहत अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने आरोपों की 'विस्तृत जांच' की लेकिन यह पता नहीं चल सका कि जानकारी कथित रूप से कैसे लीक हुई. स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी तफ्तीश के दौरान उन अधिकारियों/कार्यालयों का पता नहीं लगा सके जहां से जांच का विवरण मीडिया के साथ साझा किया गया था. अदालत को बताया गया कि प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मीडिया कर्मियों से पूछताछ की गई लेकिन उन्होंने 'अपने सूत्रों का विवरण' देने से मना कर दिया और निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि मामलों की फाइलों को अधिक मुस्तैदी से संभाला जाए ताकि ऐसे मुद्दे भविष्य में न उपजें. दिल्ली पुलिस ने कहा कि तन्हा के स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र तन्हा ने पिछले साल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले ही मुख्य आरोप पत्र में शामिल खुलासा करने वाले उनके बयान को कथित रूप से लीक करके पुलिस अधिकारियों ने कदाचार किया है.

दिल्ली में जलजमाव की शिकायत का तत्काल होगा समाधान, इस नंबर पर करें शिकायत

नई दिल्ली । दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी समस्या को हल्के में न लें. जैन ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लेना होता है. उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली में मानसून के दौरान जलजमाव की किसी भी तरह की शिकायत के तत्काल समाधान के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए. जैन ने कहा, 'नालों के रख-रखाव और नालों से गाद निकालने के अलावा जरूरत पड़ने पर नए नालों का निर्माण भी किया जाए, ताकि दिल्ली के लोगों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े. गुरुवार को पीडब्ल्यूडी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में मॉनसून के बाद की स्थिति पर चर्चा की. इस मौके पर पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे. पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 'चाहे वह नालों का रखरखाव हो, उनकी सफाई करना हो, उनसे गाद निकालना हो या आवश्यक पड़ने पर नए नालों का निर्माण करना हो, न केवल नरेला में बल्कि शहर में कहीं भी हो, जल्द से जल्द किया जाना चाहिए. ताकि दिल्ली के लोगों को जलभराव के कारण किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.'

अधिकारी शिकायत के लिए सतर्क रहें- जैन ने अधिकारियों को दिल्ली के किसी भी हिस्से से आने वाली जलजमाव की शिकायत के लिए सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया है. मंत्रालय पूरे मानसून के मौसम में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठकें आयोजित करने में सक्रिय रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली में जलभराव के कारण लोगों को किसी भी तरह की समस्या न हो.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने पर देना होगा लोकेशन और ग्रीन बेल्ट चार्ज, इसके दायरे में आएंगे ये क्षेत्र

नोएडा । ग्रेटर नोएडा और नोएडा के कुछ खास इलाकों में अब घर बनाना आसान नहीं होगा. जमीन खरीदने पर अब सर्किल रेट के साथ-साथ लोकेशन और ग्रीन बेल्ट चार्ज भी चुकाना होगा. इसके लिए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने कुछ सेक्टर को चिह्नित किया है. यहां 10 फीसद तक लोकेशन चार्ज देना होगा. वहीं ग्रीन बेल्ट के लिए 5 फीसद रकम चुकानी होगी. बिना लोकेशन और ग्रीन बेल्ट चार्ज चुकाए जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी. दूसरी ओर प्रशासन सर्किल रेट भी बढ़ाने जा रहा है. जानकारों की मानें तो गौतमबुद्ध नगर प्रशासन मेट्रो रेल कॉरिडोर और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के किनारे होने वाली जमीन की खरीद-फरोख्त पर लोकेशन चार्ज वसूलेगा. नए नियमों के तहत मेट्रो रेल कॉरिडोर और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर एक किमी के दायरे में होने वाली जमीन की खरीद पर 5 से 10 फीसदी तक लोकेशन चार्ज लगेगा. लोकेशन चार्ज रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी पर देना

गाजियाबाद में शिवरात्रि के अवसर पर एक मंदिर में महिला श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करती हुई।

वारदात वाली जगह पहुंची फोरेंसिक एसपर्ट की टीम, केस से जुड़े लोगों से पूछताछ

नई दिल्ली । दिल्ली कैंट इलाके के नांगल विलेज में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच की फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम शुक्रवार को मौका-ए-वारदात पर गई। श्मशान गृह पर फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सुबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। यहीं पर करंट लगने से मौत का दावा आरोपियों ने किया था और फिर श्मशान घाट पर ही लाश को जलाया गया था। पुलिस अधिकारी का कहना है की फोरेंसिक टीम बच्ची के घर से लेकर श्मशान गृह तक के रास्तों पर सुबूत जुटा रही है। केस से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, शवदाह से पहले हो चुकी थी मौत!- उधर, दिल्ली कैंट में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में श्मशान भूमि से मिले अवशेष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शव को जलाया जा रहा था, तब बच्ची की मौत हो चुकी थी। हालांकि, फोरेंसिक विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट पर विशेषज्ञों के एक और पैनल को अपनी राय देनी है। इसके बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकलेगा।

सूत्रों के अनुसार, शव के अवशेषों के पोस्टमार्टम के नतीजों से इससे अधिक की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती है। घटनास्थल पर आरोपितों से उनके कपड़ों के नमूने, पुजारी के आराम कक्ष की चादर व अन्य सामान की फोरेंसिक जांच में कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं। जांच में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पीड़ित बच्ची ने घटना के दिन जो कपड़े पहने थे, वे जल चुके हैं। हालांकि जले हुए कपड़ों के अवशेष को प्रयोगशाला में जांच के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दी शिकायत- वहीं, ओल्ड नांगलराय गांव की दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के निर्देशानुसार दिल्ली कांग्रेस के विधिक एवं मानव अधिकार विभाग की लीगल टीम ने बृहस्पतिवार को इस बाबत आयोग के सदस्य जस्टिस पीसी पंत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने टीम गठित करने की मांग की है।

डीयू के कॉलेजों में कक्षाएं शुरू किए जाने का फैसला स्वागतयोग्य

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को 16 अगस्त से खोले जाने का फैसला लिया गया है, जो सर्वथा उचित है। तकरीबन डेढ़ साल पूर्व कोरोना संक्रमण के गहराने के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान डीयू को बंद किया गया था, जिसके बाद से यहां कक्षाओं का संचालन पूरी तरह बंद था। छात्रों की पढ़ाई व परीक्षाएं आनलाइन हो रही थीं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए डीयू कैंपस और इसके कॉलेजों में कक्षाएं शुरू किए जाने का फैसला स्वागतयोग्य है। हालांकि, दिल्ली विश्वविद्यालय में फिलहाल सिर्फ विज्ञान वर्ग की कक्षाएं ही संचालित करने का फैसला किया गया है, जो कोरोना संबंधी नियमों का पालन कराने के दृष्टिकोण से उचित है।

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होने के कारण सारा कामकाज अब धीरे-धीरे पटरी पर आ चुका है। यही नहीं, कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं या खोलने की बात शुरू हो गई है। यह भी आसानी से समझा जा सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाई कक्षाओं में होने वाली शिक्षा का विकल्प कभी नहीं हो सकती।

विज्ञान वर्ग में छात्रों को प्रयोगशाला के इस्तेमाल की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि हालात ठीक हैं तो कक्षाएं शुरू की ही जानी चाहिए। यह अवश्य है कि कक्षाएं शुरू करने के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय या कालेजों में कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का उल्लंघन न होने पाए। शारीरिक दूरी के नियम का पूरी तरह पालन किया जाए और मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी सुनिश्चित कराया जाए।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ को भी कक्षाएं शुरू होने के दौरान छात्रों से कोरोना संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने में विश्वविद्यालय प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि पूरी सावधानी बरतते हुए सजगता के साथ कक्षाएं शुरू होंगी तो जल्द ही मानविकी और वाणिज्य वर्ग की कक्षाएं भी शुरू हो सकेंगी और विश्वविद्यालय व कालेजों का कामकाज पूरी तरह सामान्य हो

दिल्ली सरकार को मास्टर प्लान में सुझावों का ड्राफ्ट सौंपेंगे व्यापारी: बृजेश गोयल

नई दिल्ली । चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि मास्टर प्लान को लेकर व्यापारियों के मिले सुझावों का ड्राफ्ट दिल्ली सरकार को सौंपा जाएगा। इसके लिए दिल्ली के एक हजार से अधिक कारोबारी संगठनों संपर्क कर उनसे सुझाव मांगें गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा मास्टर प्लान- 2041 को अंतिम रूप देने की तैयारियां चल रही है। इसे लेकर वह नियमित रूप से दिल्ली वालों से सुझाव ले रहा है।

इसी क्रम में दिल्ली के व्यापारी भी दिल्ली सरकार के माध्यम से डीडीए को अपना सुझाव भेजेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मास्टर प्लान-2041 का मुद्दा उठाया था तथा डीडीए द्वारा मास्टर प्लान के लोगों के सुझाव के लिए रखे मसौदे को नई बोतल में पुरानी शराब जैसा बताया।

इस पर उप मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से कहा कि वे इस मुद्दे पर अपने सुझाव उन्हें दें। वह इस मुद्दे को डीडीए के समक्ष रखेंगे। बृजेश गोयल ने कहा कि इसके लिए सभी व्यापारिक संगठनों को सुझाव देने का आग्रह किया गया है। जिसे अगले सप्ताह एक ड्राफ्ट के रूप में उप मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। अब तक मिले सुझावों में दिल्ली में गोदामों और वेयरहाउस के लिए एक ठोस नीति, कनाट प्लेस, चांदनी चौक व सदर बाजार जैसे ऐतिहासिक बाजारों के विकास का रोडमैप, पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों को स्थानांतरित करने की ठोस व्यवस्था, बाजारों को जाम से मुक्ति समेत अन्य मांगें है।

जलभराव रोकने पर है जोर: शिखा राय वहीं, ग्रेटर कैलाश वार्ड की पार्षद शिखा राय ने बताया कि बारिश के दौरान वार्ड में कहीं भी जलभराव न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए निगम के सभी सफाई कर्मियों के साथ ही अन्य अधिकारियों के साथ बराबर बैठक कर कार्ययोजना बनाई जा रही है और उस पर अमल किया जा रहा है। शिखा राय ने बताया कि वार्ड की सभी छोटी नालियों की नियमित रूप से सफाई, फिर उनसे निकली सिल्ट को तुरंत हटवाना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि वार्ड में सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिलेंगी विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली । दिल्ली स्पो र्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक यूनिवर्सिटी के डिजाइन लेआउट की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी7 बैठक में पीडब्ल्यूडी, उच्च शिक्षा निदेशालय एवं यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने भाग लिया। उपमुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री ने यूनिवर्सिटी के डिजाइन की समीक्षा की और उसमें सुधार को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सिसोदिया ने कहा, यूनिवर्सिटी का निर्माण खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रख कर किया जाना है। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहां खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करने के साथ-साथ उनकी स्वस्थ जीवन-शैली के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद हों। इससे हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और वो देश के लिए मेडल जीत सकेंगे।

सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स की नवीनतम तकनीक और उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। इससे उनका ओवरआल वेल- बीइंग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार, देश के लिए पदक जीतने वाली खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की दिशा में काम कर रही है। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण लगभग 80 एकड़ भूमि में किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हाकी, एथलेटिक्स सहित लगभग सभी प्रमुख खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी।

इमरान हुसैन ने कसाबपुरा में विकास कार्यों का लिया जायजा- वहीं, दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर समस्याओं के साथ विकास कार्यों की स्थिति जानी। उनके साथ दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, नगर निगम, राजस्व विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारी सहित क्षेत्र के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे।

मंत्री ने पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआइबी इंजीनियरों को मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसी तरह अतिक्रमण और अवैध कब्जे को शीघ्रता से हटाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, डीयूएसआइबी या पीडब्ल्यूडी की किसी भी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वालों के लिए अच्छी खबर, जनहित में यूपी पुलिस करेगी ये काम

नई दिल्ली/नोएडा । दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अब बिल्डर और सोसाइटियों के बीच के झगड़े को निपटाने का जिम्मा उठाया है। दोनों पक्षों के झगड़ों को लेकर न केवल ग्रेटर नोएडा पहल करेगी, बल्कि बिल्डर और सोसायटी निवासियों के बीच आम सहमति बनाने की भी कोशिश करेगी। खासकर पुलिस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटियों और बिल्डर के झगड़ों का निपटारा भी करेगी। पिछले दिनों ग्रेटर पुलिस ने इसको लेकर नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन के साथ एक बैठक भी की।

बिल्डर-सोसायटी निवासी के बीच टकराव को भी टालेगी ग्रेटर नोएडा पुलिस- ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 50 से अधिक सोसायटी में लाखों लोग रहते हैं। इन सोसायटी में बिजली, पानी और मेंटेनेंस को लेकर अक्सर लोगों और बिल्डर प्रतिनिधियों के बीच झड़प होती रहती है। कई बार तो पुलिस को मामला सुलझाने के लिए दखल देना पड़ता है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए अब बिल्डर और सोसाइटियों के बीच के झगड़े को निपटाने का जिम्मा ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उठाया है। पिछले दिनों इस विषय पर नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन के साथ एक बैठक भी। नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान की मानें तो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ज्यादातर सोसायटी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे अक्सर बिल्डर प्रतिनिधि-कर्मचारियों और बिल्डरों के बीच टकराव होता रहता है। इनमें बिजली-पानी के अलावा मेंटेनेंस जैसी समस्या भी है। इनमें बिल्डिंग मैटिरयल से लेकर पार्किंग तक के गंभीर विवाद होते हैं।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में किसे बड़ा मुद्दा बनाने की चल रही तैयारी

नई दिल्ली । बाला साहिब अस्पताल 19 वर्षो बाद भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के पिछले दो चुनावों में यह बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। इसी के सहारे शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) को डीएसजीएमसी में सत्ता मिली है। इस चुनाव में भी इसे लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पिछले माह इस अस्पताल परिसर में देश का सबसे बड़ा डायलिसिस केंद्र शुरू किया गया है। इसके साथ ही 125 बिस्तरों वाला कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। शिअद बादल इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रहा है। वहीं, विरोधी पार्टियां इसे लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। वर्ष 2002 में 12 एकड़ जमीन पर पांच सौ बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनाने का काम शुरू हुआ था। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली (सरना) के कार्यकाल में इसे लेकर एक निजी अस्पताल के साथ समझौता किए जाने पर विवाद शुरू हुआ था। शिअद बादल ने तत्कालीन अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना पर अस्पताल को बेचने व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। वर्ष 2013 के चुनाव में यह चुनावी मुद्दा बना व सरना को पराजय का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। वर्ष 2017 के चुनाव में भी यह मुद्दा उठा था। इस वर्ष मार्च में यहां सौ मशीन के साथ डायलिसिस केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही इसी परिसर में कोरोना अस्पताल बनाने का काम चल रहा है।

डीएसजीएमसी ने सात अगस्त को इसके उद्घाटन की घोषणा की है। शिअद बादल के प्रदेश अध्यक्ष व डीएसजीएमसी के महासचिव हरमीत सिंह कालका का कहना है कि कमेटी मानवता की सेवा के लिए काम कर रही है। वहीं, सरना का आरोप है कि चुनाव में लाभ उठाने के लिए बगैर जरूरी मंजूरी के और आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था किए बिना डायलिसिस केंद्र शुरू किया गया है। उनका कहना है कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। पिछले दिनों अदालत ने भी उन्हें बरी कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि शिअद बादल ने चुनावी लाभ के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे।

अस्पताल के निर्माण कार्य को भी बाधित किया गया। जग आसरा गुरु ओट (जागो) के नेता भी इस केंद्र को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधी नेताओं का कहना है कि पांच सौ बिस्तरों का अस्पताल बनाने के बजाय इसके कुछ हिस्से का उद्घाटन किया जा रहा है।

संपादकीय

अपने सागर की सुरक्षा का इंतजाम

लंबे समय से उपेक्षित भारत के समुद्री क्षेत्र को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक मतलब नेशनल मैरीटाइम सिक्युरिटी कोर्डिनेटर (एनएमएससी) की नियुक्ति के साथ फिर से एकसूत्र किया जाएगा। माना जा रहा है, यह समन्वयक समुद्री सुरक्षा के मामले में सरकार का प्रमुख सलाहकार होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी एनएसए के अधीन काम करेगा और उम्मीद है कि देश के विशाल समुद्री विस्तार का प्रबंधन करने वाले केंद्र के अलग-अलग मंत्रालयों व विभागों के साथ देश के तटीय राज्यों में जरूरी तालमेल बनाने का काम करेगा। यह एक स्वागतयोग्य पहल है, हालांकि इसका अरसे से इंतजार था। समुद्री मामलों की समग्रता से देख-रेख करने वाली ऐसी किसी व्यवस्था की जरूरत 2008 में मुंबई के 26/11 हमले के बाद ही महसूस की गई थी। उस हमले ने बेपरदा कर दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले किसी बड़े खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए केंद्र व राज्य (महाराष्ट्र) की बीच समन्वय की भारी कमी है। अब 13 साल के बाद (जो हमारी धीमी रफ्तार बताता है) वह प्रस्ताव इस तरह हकीकत बनने जा रहा है। रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही इस पद को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। बेशक इससे इनकार नहीं है कि मुंबई हमले के बाद तटीय सुरक्षा, विशेषकर तटरक्षक (सीजी) पर काफी ध्यान दिया गया और उनके लिए फंड मुहैया कराए गए, फिर भी तटीय सुरक्षा में सैन्य दस्तों को सुसंगत बनाने की आवश्यकता बनी हुई है और राज्य की समुद्री पुलिस इकाइयों को भी अभी तक जरूरी क्षमताओं से लैस नहीं किया गया है। यही नहीं, नौसेना और तटरक्षक के बीच हालिया मतभेद को भी दूर करने की जरूरत है। एनएमएससी को सौंपे जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का चार्टर ही यह स्पष्ट कर देगा कि उनके लिए आखिर क्या सोचा गया है, लेकिन कुछ खास बातों पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। 26/11 के बाद किसी वरिष्ठ नौसैन्य अधिकारी को समुद्री सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन यह फाइल दिल्ली की महान नौकरशाही व्यवस्था में उलझकर रह गई और धीरे-धीरे नीतिगत रडार से ही गायब हो गई। यह माना जाता है कि सलाहकार शब्द को उस समय ज्यादा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसा मालूम पड़ रहा था।

वर्ष 2003 में सागरमाला परियोजना के साथ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने समुद्री क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया, मगर यह साकार नहीं हो सकी। इसके बाद, 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास योजना (एनएमडीपी) बनाई, लेकिन यह भी योजनानुसार इस क्षेत्र को नया जीवन नहीं दे सकी। यानी, महासागरों को लेकर आधा-अधूरा प्रयास होता रहा।

ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समुद्री क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का श्रेय दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 2015 में हिंद महासागर के एक द्वीप के दौरे के दौरान 'सागर' (सिक्युरिटी ऐंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी इस क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के लिए सुरक्षा और विकास) शब्द गढ़ा। हालांकि, इस सोच को साकार करने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत थी, जिसमें मोदी 1.0 की कैबिनेट की क्षमता और रक्षा मंत्रियों की लगातार विदाई (पांच साल के कार्यकाल में चार मंत्री) अड़चन बनी रही। हालांकि, हाल के वर्षों में, नीति आयोग ने समुद्री क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान देना शुरू किया, और देश की नीली अर्थव्यवस्था (आर्थिक गतिविधियां, जिनमें समुद्र व उसके संसाधनों का इस्तेमाल होता है) पर केंद्रित नीतियां वाकई में उत्साहवर्द्धक हैं। मगर इसे सफलतापूर्वक हकीकत बनाने में हमारे सामने कई मुश्किलें आएंगी, जहां प्रस्तावित एनएमएससी मददगार हो सकते हैं।

पहली नजर में, प्रस्तावित प्रमुख सलाहकार की यह व्यवस्था मौजूदा रक्षा क्षेत्र के उच्च प्रबंधन के समान जान पड़ती है। अभी नौसेना प्रमुख (सीएनएस) के पास यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और थिएटर कमांडरों के पद के सृजन के साथ फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। जाहिर है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर गंभीर बदलाव अब हमारी नीतियों का हिस्सा है। फिलहाल, यही माना जा सकता है कि एनएमएससी कहीं ज्यादा समग्रता से समुद्री सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे, क्योंकि देश की समग्र समुद्री सुरक्षा (सीएमएस) थल सेना अथवा नौसेना की मुस्तैद सुरक्षा की तुलना में बहुत व्यापक है। व्यापक समुद्री सुरक्षा भू-रणनीतिक व भू-राजनीतिक नीतियों का अंग है और इंडो-पैसिफिक व क्वाड के गठन को देखते हुए हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। भू-आर्थिकी (व्यापार, ऊर्जा, मछली पकड़ना और समुद्री तल का खनन) और भू-भौतिक (पर्यावरण और पारिस्थितिक निर्धारकों को महासागरों की सेहत का हिस्सा बनाना) इसी समुद्री सुरक्षा के अन्य दो पहलू हैं। स्पष्ट है, समुद्रों और महासागरों पर भारत की निर्भरता बहुत ज्यादा है। यहां व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और मछली पकड़ना तो जगजाहिर है, लेकिन इसके साइबर पक्ष को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जबकि वैश्विक साइबर-डिजिटिल कनेक्टिविटी तभी संभव है, जब पानी के नीचे तारों का जाल बिछाया जाए। इस प्रकार, एनएमएससी को समुद्री चुनौतियों से जूझना होगा और अवसरों का अधिकाधिक लाभ भी उठाना होगा। भारत के मरणासन्न समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सर्वप्रथम नियुक्त होने वाले समन्वयक का कौशल काफी मायने रखेगा। एक तथ्य यह भी है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था और बड़ी ताकत बनने की इच्छा तो रखता है, लेकिन उसके पास एक भी ऐसा बड़ा बंदरगाह नहीं है, जो सामान की ढुलाई और बंदरगाह दक्षता सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शुमार हो। भारतीय समुद्री पेशेवर भी यही रोना रोते हैं कि नई दिल्ली में बैठे नीति-निर्माता उनकी योग्यता व क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते, और वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नजरअंदाज करते हैं। लिहाजा, उम्मीद की जानी चाहिए कि एक राष्ट्रीय समुद्री शेरपा, यानी एनएमएससी 'सागर' को हकीकत बनाने और देश की विशाल समुद्री क्षमता के विवेकपूर्ण इस्तेमाल की राह आसान करेंगे।

प्रवीण कुमार सिंह

राजद्रोह कानून का दुरुपयोग गंभीर बात है, लेकिन विचारणीय है उसकी जरूरत और उपयोगिता

उनके अनुसार इस कानून का सुनिश्चित उद्देश्य व प्रयोजन है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। यह खूबसूरत मौलिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता अखंडता के तोड़कों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई का कानून भी जरूरी है। राजद्रोह असाधारण प्रकृति का अपराध है। इसलिए कानून की उपयोगिता है। इस दृष्टि से वेणुगोपाल के सुझाव उपयोगी हैं। मूल समस्या कानून के दुरुपयोग की है, कानून समाप्त करने की नहीं है। माननीय न्यायालय ने समग्रता में सुनवाई व विचारण की बात कही है। विश्वास है कि समग्रता में विचारण का फल राष्ट्र हितैषी होगा।

भारतीय राष्ट्र राज्य संप्रभु सत्ता है। व्यक्ति की तरह राष्ट्र राज्य की भी अस्मिता है। राष्ट्र को भी आत्मरक्षा के अधिकार हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आइपीसी की धारा-121, 121ए, 122, 123, 124 व 124ए में राजद्रोह से निपटने के प्रविधान हैं। इनमें से 124ए के दुरुपयोग और खात्मे पर बहस जारी है। इस कानून में उल्लेख है, 'जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या उसकी कोशिश करेगा। अप्रीति का प्रसार करेगा, प्रयत्न करेगा वह तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।' सर्वोच्च न्यायपीठ ने इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 'सरकार ने कई पुराने कानून रद किए हैं। गांधी और तिलक के विरुद्ध भी इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। क्या स्वतंत्रता के बाद भी इस कानून की जरूरत है?' कानून का दुरुपयोग बेशक गंभीर बात है, लेकिन कानून की आवश्यकता भी विचारणीय है। आवश्यकता से ही कानून का जन्म होता है। कानूनों में संशोधन और निरसन भी राष्ट्र की आवश्यकता के कारण ही होते हैं। कानून का मसौदा विधेयक पेश करते समय प्रस्तावित विधि के उद्देश्य और कारण बताए जाते हैं।

राजद्रोह कानून के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप दुरुपयोग का है। इसके लिए कानून का उपयोग करने वाला तंत्र जिम्मेदार है, कानून नहीं। अवैध हथियार रखना अपराध है। इसके लिए शस्त्र अधिनियम है। यह कानून समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन पुलिस इसी कानून में निर्दोषों को भी जेल भेजती है। क्या इसी आधार पर कानून समाप्त करना सही हो

सकता है? यहां तमाम कानूनों का दुरुपयोग होता है, लेकिन मात्र दुरुपयोग के आधार पर ही कानून समाप्ति का कोई औचित्य नहीं है। दुरुपयोग रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए कानून प्रवर्तित करने वाले तंत्र के पेच कसने की जरूरत है। राजद्रोह संबंधी कानून के विरुद्ध दूसरा मुख्य आरोप विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होना है। विचार अभिव्यक्ति संविधान का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह निरपेक्ष और असीम नहीं है। इससे जुड़े अनुच्छेद 19 में विचार स्वातंर्त्य पर 'भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था और न्यायालय अवमान आदि के बंधन' हैं। यहां विचार अभिव्यक्ति के बहाने राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता से खिलवाड़ की छूट नहीं है। ऐसा खिलवाड़ देशद्रोह की श्रेणी में क्यों नहीं आ सकता?

राजद्रोह कानून की संवैधानिकता का परीक्षण उचित है। वर्ष 1962 में सर्वोच्च न्यायपीठ ने केदारनाथ मामले में 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण किया था और इसे संवैधानिक घोषित किया था। यह भी कहा था कि 'नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है बशर्ते वे हिंसक विचार से दूर रहें।' भारत में सरकारों की आलोचना होती है। असहमति के अवसर हैं। वैचारिक टकराव भी हैं। मूलभूत प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता पर भी आक्रमण करना सिर्फ सरकार की ही आलोचना है? भारतीय देश से भावात्मक लगाव रखते हैं। देश की धरती को भारत माता कहते हैं। वंदे मातरम् हमारा राष्ट्रगीत है। पं. नेहरू ने भी 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में देश की धरती और लोगों को भारत माता बताया है। भिन्न-भिन्न समूहों द्वारा भावनाएं आहत होने की चर्चा बहुधा चलती है। राष्ट्रीय अखंडता का अपमान देशद्रोह की श्रेणी में क्यों नहीं आ सकता? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजद्रोह की चर्चा इन शब्दों में की है, 'यदि साम आदि उपायों से राजद्रोहियों को शांत न किया जा सके तो दंड का प्रयोग होना चाहिए।'

राजद्रोह राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती है। भारत में राजद्रोह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। कभी करनी द्वारा और बहुधा कथनी द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नारेबाजी हुई, 'भारत तेरे टुकड़े होंगे।' इस नारेबाजी को राजद्रोह नहीं तो क्या सुभाषित की श्रेणी में रखेंगे? दूसरी नारेबाजी और भी आग लगाऊ है, 'अफजल हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा हैं।' यह दोष सिद्ध भारत विरोधी राजद्रोही आतंकी का महिमामंडन है। क्या यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खतरनाक दुरुपयोग नहीं है? इसे राजद्रोह की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता? पाकिस्तानी झंडे लहराना राष्ट्रीय अखंडता व संप्रभुता पर सीधा हमला है। यह सरासर राजद्रोह है। माओवादी हिंसा राष्ट्र राज्य से युद्ध है। ऐसी घटनाएं विचार और मंसूबे देशद्रोह हैं। ये राजद्रोह की ही श्रेणी में आती हैं। आइपीसी की धारा 124ए में इनका विचारण संभव है। राष्ट्र राज्य की अस्मिता का विधिक संरक्षण जरूरी है। भारत में विधि का शासन है। यहां हर समस्या का समाधान विधि द्वारा ही होता है।

सक्रिय राष्ट्र विरोधी शक्तियों से निपटने के लिए कानून जरूरी हैं। ये ताकतें किसी न किसी रूप में अपने मंसूबे पूरे करने में लगी हैं। आतंकियों की हरसंभव सहायता यही ताकतें करती हैं। राष्ट्र की आंतरिक रक्षा के लिए 124ए की अपनी उपयोगिता है। इसके दुरुपयोग की चर्चा नई नहीं है। दुरुपयोग रोकने के लिए इसी कानून में कतिपय संशोधन संभव हैं। विधि प्रवर्तक तंत्र को भी दुरुस्त करना होगा। इस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय की यह बात सही है कि इस कानून में जवाबदेही नहीं है। अदालत ने इस कानूनी प्रविधान की संवैधानिकता जांचने का निश्चय किया है। यह अच्छी बात है, पर संवैधानिकता के साथ इसकी उपयोगिता का निरीक्षण भी जरूरी है। दुनिया के सभी कानूनों का उद्देश्य उपयोगिता ही होता है। उपयोगिता समाप्ति के बाद कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब उसकी समाप्ति ही उचित है।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा है कि 'राजद्रोह कानून पर विचार अभिव्यक्ति के लिटमस टेस्ट से परीक्षण का समय आ गया है।' अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने तर्क दिया है कि दुरुपयोग रोकने के लिए, 'कुछ मार्गदर्शी रक्षोपाय जोड़कर कानून का सही लक्ष्य पाया जा सकता है।' उनके अनुसार इस कानून का सुनिश्चित उद्देश्य व प्रयोजन है।

विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। यह खूबसूरत मौलिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता अखंडता के तोड़कों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई का कानून भी जरूरी है। राजद्रोह असाधारण प्रकृति का अपराध है। इसलिए कानून की उपयोगिता है। इस दृष्टि से वेणुगोपाल के सुझाव उपयोगी हैं। मूल समस्या कानून के दुरुपयोग की है, कानून समाप्त करने की नहीं है। माननीय न्यायालय ने समग्रता में सुनवाई व विचारण की बात कही है। विश्वास है कि समग्रता में विचारण का फल राष्ट्र हितैषी होगा।

गरीब की गरीबी ही सबसे बड़ी समस्या, साधनहीनता भी स्त्री-पुरुषों में बंट गई

हवा में चुनावों की चर्चा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर। इसके बाद कुछ और राज्यों के चुनाव। जैसे ही चुनाव आते हैं, विभिन्न जातियों, धर्मों और उनसे जुड़े दल अपने-अपने घोषणापत्र लेकर हाजिर हो जाते हैं। नए समीकरण बनने लगते हैं। आज तक जो विरोधी था, वह दोस्त हो जाता है और दोस्त पानी पी-पीकर कोसने लगता है। यही हाल दूसरे समूहों का होता है। कोई महिलाओं के नाम पर, कोई ट्रांसजेंडर तो कोई पर्यावरण के नाम पर अपनी-अपनी मांगें उठाने लगता है। पिछले कुछ दशकों में जैसे-जैसे महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है और वे वोट का गुणा-भाग करने लगी हैं, वैसे-वैसे हर दल उनका हितैषी दिखने की कोशिश करने लगे हैं। अपने-अपने दलों के घोषणा पत्रों में उन्हें विशेष जगह दी जाने लगी है। आधी आबादी की निर्णयकारी क्षमता से दल घबराने लगे हैं। वे उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते दिखते हैं, लेकिन जब एक वर्ग, समूह को आप अपनी तरफ खींचते हैं तो अक्सर दूसरे समूह पीछे रह जाते हैं और वे अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि विमर्श से, बहसों से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। समझा यह जाता है कि ये समूह कहां जाएंगे। हमें ही वोट देंगे, लेकिन यह सच नहीं है।

जब सरकारें किसी एक तरफ ध्यान देती हैं तो दूसरी तरफ इसकी प्रतिक्रिया होती दिखाई देती है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में ये प्रतिक्रियाएं धीमी हों और उनकी आवाजों को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन चुनावी गणित में हाशिये की ये आवाजें अपने करतब दिखा देती हैं। आप सोचेंगे कि आखिर इन दिनों कौन सी वे आवाजें हैं, जिन्हें हाशिये की आवाजें कहा जा रहा है। ये आवाजें हैं- पुरुषों की। बहुत से लोग यह पढ़कर नाक-भौं सिकोड़ सकते हैं। इस लेखिका को स्त्री विरोधी होने का तमगा भी दे सकते हैं, लेकिन डरकर सच बात कहने से अगर रुक जाएं तो फिर लिखना, सोचना, समझना सब व्यर्थ है। कितने दशक हुए जबसे आपने यह सुना कि सरकार गरीब पुरुषों के लिए भी कोई योजना बना रही है? उनकी पढ़ाई, लिखाई, रोजगार, चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है? कह सकते हैं कि आखिर पुरुषों को इस तरह की योजनाओं की क्या जरूरत? वे तो पहले ही हर निर्णयकारी जगह पर बैठे हैं यानी यह मान लें कि पुरुष न तो गरीब होते हैं, न साधनहीन, न उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है, न ही वे बेरोजगार होते हैं और न ही उनके मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है। परिदृश्य में हम देखते हैं कि पुरुषों की छवि इन दिनों किसी ऐसे खलनायक की बना दी गई है, जिसके जीवन में कोई दुख ही नहीं। जिस किसान-मजदूर की चिंता में हम दुबले हुए जाते हैं, जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता में हाहाकार करते हैं, क्या वे पुरुष नहीं हैं? इस पर गौर करें कि गरीब और साधनहीन पुरुष किसी विमर्श का हिस्सा नहीं हैं। वे मात्र पिटने और नफरत करने लायक हैं। सारे पुरुष या मर्द होते ही ऐसे हैं का मुहावरा इस कदर चल पड़ा है कि हमें वर्गों की खाई दिखाई देना बंद हो गई है। वे तो पैदा ही इसलिए होते हैं कि दूसरों को सता सकें, लेकिन क्या बिल गेट्स और उनका ड्राइवर पुरुष होते हुए भी एक जैसे होंगे। किसी दफ्तर का सबसे बड़ा अधिकारी और चाय-पानी पिलाने वाले लड़के की समस्याएं एक तरह की हो सकती हैं।

दरअसल इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं, उनकी समस्याएं कैसी हैं, कितनी तरह की हैं, वे ही बता सकते हैं। किसी की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती, लेकिन पिछले पांच दशक से अधिक समय में अपने देश में पुरुषों की छवि ऐसी बना दी गई है, मानो बस वे ही हैं, जिनके कारण यह धरती नर्क बनी हुई है। वे न होते, तो सब ठीक होता। जबकि हमें मालूम है कि इस धरती को हर तरह से जिन्होंने दुहा है, जिनका भगवान ही उनका मुनाफा है, वे इस तरह की बातों और सोच से साफ बच जाते हैं। असली खलनायकों को अक्सर भुला दिया जाता है।

क्या हम दूसरों के हिसाब से बदल सकते हैं

कई दशक पहले मेरे यहां गैस का सिलेंडर देने एक युवा आता था। एमए-एमएड था, मगर कहीं नौकरी नहीं मिली। उसकी सबसे बड़ी समस्या ढंग के रोजगार की थी, क्योंकि वह घर में अकेला कमाने वाला था। उसका कहना था कि उस जैसे लोगों की कोई नहीं सुनता, क्योंकि वह गरीब है। सारे पुरुषों को खदेड़कर हम क्या करना चाहते हैं? ध्यान रहे कि जिन समाजों में स्त्रियां खुद मुख्तार हैं, वहां भी सारी समस्याएं हल नहीं हो गई हैं। लोग कहते हैं कि पुरुषों की आलोचना का मतलब उनके बदलने से है। सवाल यह है कि जब हम अपने अनुसार दूसरे के बदलाव की मांग करते हैं तो क्या कभी यह सोचते हैं कि क्या हम दूसरों के हिसाब से वैसे ही बदल सकते हैं, जैसी मांग दूसरों से कर रहे हैं? अपने देश में साधारण आदमी तरह-तरह की मुश्किलों से परेशान है, मगर खांचों का बंटवारा इन दिनों ऐसा कर दिया गया है कि गरीबी और साधनहीनता भी स्त्री-पुरुषों में बांट दी गई है। कोरोना काल में जिन लाखों को हमने अपने-अपने घरों की तरफ दौड़ते देखा, परेशान और बेहाल देखा उनमें स्त्री-पुरुष दोनों थे, मगर वे गरीब और साधनहीन ही थे, जो विपत्ति से बचने के लिए अपने घर, गांव की ओर भाग रहे थे। सच तो यह है कि गरीब की कोई जाति, धर्म, लिंग नहीं होता। गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर गरीबी न हो, तो बाकी की समस्याएं भी हल हो जाएं।

विदेशी स्टूडेंट्स को भारत आकर

पढ़ाई करने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई योजना एसआईआई (स्टडी इन इंडिया) में इस साल बढ़ी हुई भागीदारी उत्साहवर्धक है। चार साल पहले यानी 2018-19 में शुरू की गई इस योजना में विदेशी स्टूडेंट्स को भारत में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। आंकड़े बताते हैं कि जहां पिछले साल इसके लिए 20659 आवेदन आए थे, वहीं इस साल 50,739 आवेदन आए। यानी करीब 146 फीसदी की बढ़ोतरी। यही नहीं आवेदन करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स में भी इस बार पिछले साल के मुताबिक 23.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

योजना का नाम इस बार बदलकर प्रगति (परफॉरमेंस रेटिंग ऑफ ऐप्लिकेंट्स थ्रू ग्लोबल ऐप्टिट्यूड टेस्ट फॉर इंडियन इंस्टिट्यूट्स) जरूर किया गया है, लेकिन इसकी इस कामयाबी का श्रेय नए नामकरण को नहीं दिया जा सकता।

इसके पीछे उन खास बदलावों की भूमिका है, जो विदेशी स्टूडेंट्स की जरूरत और उनकी मानसिकता को समझते हुए इस योजना में किए गए हैं। पहले इस योजना में उन्हीं संस्थानों को शामिल किया गया था, जिन्हें एनएएसी (नैशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल) से 3.26 ग्रेड और एनआईआरएफ की 100 रैंकिंग हासिल हो।

यह ऐकडेमिक रैंकिंग है, लेकिन विदेशों से आने वाले स्टूडेंट्स की इकलौती चिंता रैंकिंग की नहीं होती। उन्हें हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा आदि की सहूलियतें भी देखनी होती हैं। इसलिए इस बार इस योजना में रैंकिंग के साथ-साथ स्टूडेंट्स की पसंद को भी शामिल किया गया और नतीजा सामने है। यह बताता है कि किसी भी योजना की कामयाबी के लिए उन लोगों की स्थिति, सोच और जरूरत को ध्यान में रखा जाना सबसे जरूरी होता है, जिनके लिए वह योजना लाई गई हो।

बहरहाल, इस खास योजना की कामयाबी और उसमें निहित संदेश की अहमियत स्वीकार करते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि भारत को विदेशी स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन हब बनाने का हमारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है।

भारत आकर पढ़ाई करने वाले कुल विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में 49,348 थी, जो 2018-19 के 47,427 से कुछ ही ज्यादा थी। इस साल उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है यह देखना पड़ेगा, लेकिन जो भी बढ़ोतरी हो इसे दो लाख स्टूडेंट तक पहुंचाने का लक्ष्य अभी काफी दूर है।

अफगान सरकार और तालिबान के बीच सुलह का रास्ता निकले बिना चलता रहेगा हिंसा का दौर

अब भारत के हित में यही है कि वह वास्तविकता को स्वीकार करते हुए तालिबान से वार्ता करे, भले ही उसकी कड़ियां पाकिस्तान से क्यों न जुड़ी हों। ऐसा करके भारत तालिबान की कट्टरपंथी सोच पर मुहर नहीं लगाएगा। वास्तव में ऐसे संवाद से वह उसे यह बता सकता है कि दुनिया मध्यकालीन विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगी। कूटनीति तो उन लोगों से भी संपर्क की मांग करती है, जिनके विचार हमारे राष्ट्रीय सिद्धांतों के एकदम खिलाफ होते हैं। समय की यही मांग है कि राष्ट्रीय हितों के लिए दुश्मन देश के दोस्त से भी बात की जाए।

अफगानिस्तान में जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं। हाल में तालिबान ने देश के कई इलाकों पर अपना शिकंजा और कसा है। उत्तर पूर्व, उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में उसकी पैठ और मजबूत हुई है। अफगान सरकार भले ही यह दावा करे कि सुरक्षा स्थिति अभी भी उसके नियंत्रण में है, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। कंधार की सुरक्षा स्थिति भी खराब है। इसे देखते हुए भारत ने वहां स्थित अपने वाणिज्य दूतावास के भारतीय कर्मियों को गत सप्ताह वापस बुलाने का फैसला किया। यह बिल्कुल सही था, क्योंकि इन कर्मियों को खतरे में नहीं झोंका जा सकता था। गत वर्ष भी भारत ने जलालाबाद और हेरात स्थित अपने वाणिज्य दूतावास बंद किए थे। उसके पीछे आधिकारिक वजह कोरोना महामारी को बताया गया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार को आभास हुआ कि ये दोनों अफगान शहर भारतीय स्टाफ के लिए असुरक्षित हो गए हैं। इन वाणिज्य दूतावास बंद करने से जहां भारतीय हितों को आघात पहुंचा वहीं पाकिस्तान को संतुष्टि मिली। पाकिस्तान ने हमेशा ये मिथ्या आरोप लगाए हैं कि अफगान स्थित इन प्रतिनिधि कार्यालयों का उपयोग भारत उसके लिए समस्याएं उत्पन्न करने में करता रहा है।

फिलहाल तालिबान अमेरिकी सेनाओं की वापसी का फायदा उठा रहा है। इससे अफगानिस्तान में अनिश्चितता बढ़ गई है। इससे कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। एक तो यही कि क्या तालिबान की मौजूदा सैन्य कार्रवाई के पीछे यह वजह है कि वह अपनी स्थिति मजबूत करके अफगान सरकार से वार्ता करेगा या फिर उसने वार्ता की राह पूरी तरह छोड़ दी है और ताकत से सत्ता हथियाना चाहता है? हमारे पास अभी तक इसका जवाब नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर तालिबान सत्ता साझेदारी के आधार पर अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने पर सहमत हुआ तो वह रक्षा क्षेत्र और खुफिया एजेंसियों पर नियंत्रण की मांग करेगा। शायद अफगान सरकार इस पर राजी न हो। जो भी हो, जब तक अफगान सरकार और तालिबान के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं तलाशा जाता तब तक हिंसा और संघर्ष का दौर चलता रहेगा। इस बीच 14 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की ताजिकिस्तान में बैठक हुई। वहां अफगानिस्तान की हालत ही मुख्य मुद्दा रहा। इसमें

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अन्य सदस्य देशों चीन, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। अफगान विदेश मंत्री ने भी इसमें भाग लिया। जयशंकर ने हिंसा की समाप्ति और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। तालिबान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अगर सत्ता ताकत से हासिल की जाएगी तो उसे मान्यता नहीं मिल पाएगी। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि अफगान जनता के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उसके पड़ोसी देशों को अफगान धरती से उपजे आतंकवाद से पीड़ित न होना पड़े।

इस दौरान एससीओ विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान पर एक संयुक्त बयान भी जारी किया। इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरना चाहिए, जो हिंसा, चरमपंथ और अवैध अफीम की पैदावार से मुक्त हो। बयान में यह भी उल्लेख था कि अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों की गतिविधियां अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह हैं। एससीओ विदेश मंत्रियों ने सभी अफगान पक्षों से यह आह्वान भी किया कि वे बल प्रयोग न करें। संयुक्त बयान के अनुसार अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता के जरिये ही वहां शांति संभव है। इस सबके बीच पाकिस्तान का यही दावा है कि वह इस पक्ष में है कि अफगान लोग अपने भविष्य का फैसला खुद करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। तालिबान की मदद कर रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार है। तालिबान की सहायता करके पाकिस्तान ने उसे यह अवसर दिया कि वह सैन्य सफलता प्राप्त करे। ऐसे में जयशंकर ने उचित ही कहा कि कुछ ऐसी ताकतें भी सक्रिय हैं, जिनका अलग ही एजेंडा है। इससे यही ध्वनित हुआ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं चाहता।

सामरिक मोर्चे सहित अफगानिस्तान में भारत के व्यापक हित जुड़े हुए हैं। उसने अफगान सरकार और वहां की राजनीतिक बिरादरी के विभिन्न वर्गों से बेहतरीन संबंध बनाए हैं। काबुल की संस्थाओं का भारत के प्रति बहुत सम्मान भाव है। पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर यह जानते हुए भी कदम बढ़ाए थे कि इससे पाकिस्तान कुपित होगा। अफगानिस्तान को मदद पहुंचाकर भारत अफगान जनता में भी लोकप्रिय हुआ। इस सबके बावजूद जमीनी स्तर पर मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान की मौजूदा स्थिति यकायक मजबूत नहीं हुई है। जब स्थिति राष्ट्रहित के विपरीत बन रही हो तो सफल कूटनीति के लिए जरूरी हो जाता है कि वह मौके की नजाकत को समझे और उसी हिसाब से कदम उठाए। बीते कई वर्षों से स्पष्ट हो रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में रणनीतिक हार स्वीकार कर वहां से निकल जाएगा।

इसी कारण उसने पाकिस्तान सीमा तक युद्ध का विस्तार नहीं किया। ऐसा किए बिना तालिबान को हराया नहीं जा सकता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि अमेरिका और तालिबान में वार्ता होगी, जिससे इस समूह को एक किस्म की अंतरराष्ट्रीय वैधता मिल जाएगी। यही वास्तव में हुआ भी। जहां कई देशों ने तालिबान से सीधे संपर्क साधा, लेकिन भारत ने नहीं किया, पर वह अतीत की बात है। अब भारत के हित में यही है कि वह वास्तविकता को स्वीकार करते हुए तालिबान से वार्ता करे, भले ही उसकी कड़ियां पाकिस्तान से क्यों न जुड़ी हों। ऐसा करके भारत तालिबान की कट्टरपंथी सोच पर मुहर नहीं लगाएगा। वास्तव में ऐसे संवाद से वह उसे यह बता सकता है कि दुनिया मध्यकालीन विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगी। कूटनीति तो उन लोगों से भी संपर्क की मांग करती है, जिनके विचार हमारे राष्ट्रीय सिद्धांतों के एकदम खिलाफ होते हैं। समय की यही मांग है कि राष्ट्रीय हितों के लिए दुश्मन देश के दोस्त से भी बात की जाए।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

योगी सरकार ने पूरा किया वादा: उन्नाव में जिंदा जलाई गई गैंगरेप पीड़िता की बहन को मिली नौकरी

उन्नाव । उन्नाव जिले में जिंदा जलाकर मारी गई गैंगरेप पीडिता की बहन को अचलगंज नगर पंचायत में चतुर्थ श्रेणी पद पर नौकरी मिली है। घटना के बाद सरकार ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी का आश्वासन दिया था। बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच दिसंबर 2019 को रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने गांव के पांच लोगों को नामजद किया था, जो जेल में हैं। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर तक सुर्खियां बटोरी थीं। परिजनों की मांग पर सरकार ने पीड़ित परिवार को आवास व पीड़िता की बहन को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था। डेढ़ साल बाद पीड़िता की बहन को ज्वाइनिंग दी जा सकी। डीएम रवींद्र कुमार ने बताया कि नगर पंचायत अचलगंज में नियुक्ति दी गई है। गैंगरेप पीड़िता के जिंदा जलाए जाने की घटना के नौ महीने बाद 2 अक्तूबर 2020 को उसका छह वर्षीय भतीजा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। इसकी छानबीन दूसरे राज्यों तक की गी लेकिन जांच में जुटी पुलिस टीमें बच्चे का पता लगाने में विफल रहीं। अभी तक बच्चे का पता नहीं चला है। भतीजे के अपहरण के बाद पीड़िता की बहन की नौकरी के मामले ने तूल पकडा था। तब एसडीएम व अन्य अफसरों ने उसके दस्तावेज लेकर जल्द से जल्द नौकरी दिलवाने की बात कही थी।

कानपुर का अनस अंसारी बना अमन, पहले किया प्यार फिर घर बुलाकर गैंगरेप

कानपुर । जिले के यशोदा नगर की युवती ने नाम-धर्म बदलकर दूसरे समुदाय के युवक पर शादी का झांसा दे घर पर बंधक बनाकर भाई-पिता के साथ गैंगरेप करने की एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची। युवती ने बताया कि वह इलाके की एक साड़ी की दुकान में जॉब करती थी, जहां पर पहले से ही एक युवक काम करता था। उसने अपना नाम अमन बताया था। बातचीत के दौरान उसने शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों तैयार हो गए और घर से भाग गए। मामले में भाई ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इस बीच अमन अप्रैल में उसे अपने घर ले गया, जहां उसे पता चला कि अमन का असली नाम अनस अंसारी है। उसने नाम-धर्म बदलकर उसे फंसाया था। इस दौरान वह भागने लगी तो उसके घर वालों ने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर घर पर ही बंधक बनाकर रखा। इस दौरान अनस के घरवालों ने बहुत प्रताड़ित किया। आरोप है कि अनस के साथ-साथ उसके भाई और पिता ने मिलकर गैंगरेप किया। **भागने पर गर्म चिमटे से जलाया हाथ-** पीड़िता ने बताया कि यातनाएं सहने की क्षमता खत्म होने लगीं तो वह 30 जुलाई की सुबह अनस के घर से बैग लेकर भागने लगी। अनस की मां ने उसे पकड़ लिया। परिवार संग पीटने के बाद गर्म चिमटे से उसका बाएं हाथ को जला दिया। देर शाम वह मौका देकर भाग निकली और घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर अनस, उसके भाई-पिता और मां पर गैंगरेप, मारपीट, धमकी सहित धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। नौबस्ता इंस्पेक्टर सतीश सिंह ने बताया कि मामले में पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान कराए गए थे, जहां उसने धर्मांतरण वाली बात नहीं कही। बल्कि प्रेमी के पिता पर रेप का आरोप लगाया है। उसे जेल भेजा गया है।

बिहार पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले नीतीश कैबिनेट देगी मंजूरी, जानिए कब हो सकते हैं चुनाव

पटना । बिहार में पंचायत चुनाव की जोरो पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग को पंचायत व ग्राम कचहरियों के आम चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में अपनी अनुशंसा भेज दी है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। 20 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है।

आयोग की अनुशंसा पर पंचायतीराज विभाग राज्य मंत्रिपरिषद से अनुमति लेकर अधिसूचना जारी करेगा। अबतक परंपरा रही है कि आयोग की अनुशंसा को हु-ब-हू स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। आयोग के अनुसार राज्य में पंचायतों व ग्राम कचहरियों के विभिन्न पदों के लिए दस चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 20 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 24 सितंबर को, तीसरे चरण का मतदान 04 अक्टूबर को, चौथे चरण का मतदान 08 अक्टूबर को, पांचवें चरण का मतदान 18 अक्टूबर को, छठे चरण का मतदान 22 अक्टूबर को, सातवें चरण का मतदान 31 अक्टूबर को, आठवें चरण का मतदान 07 नवंबर को, नौवें चरण का मतदान 15 नवंबर को एवं दसवें व अंतिम चरण का मतदान 25 नवंबर को संपन्न होगा।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को नीतीश सरकार से मिलेगा मुआवजा

पटना । पटना जिला में बाढ़ से प्रभावित अंचलों में फसल क्षति का सर्वेक्षण एवं आकलन किया जाएगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची भी तैयार की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को फसल क्षति का सर्वेक्षण एवं आकलन कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया। अंचलवार कृषि समन्वयक को सूची तैयार करने का निर्देश दिया ताकि फसल क्षति के अनुरूप मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा सके। डीएम ने बताया कि चनाकी गांव में तटबंध के किनारे स्थित परिवारों की सूची धनरुआ के अंचलाधिकारी तैयार करेंगे। सूची तैयार होने के बाद प्रति परिवार 6000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अंचल के अन्य बाढ़ प्रभावित छूटे हुए परिवारों की भी सूची अविलंब अद्यतन कर तैयार अवस्था में रखने का निर्देश दिया।

कानपुर में फर्जी जमानत से अपराधियों को जेल की सलाखों से छुड़ाने का बड़ा रैकेट चल रहा

कानपुर । फर्जी जमानत से अपराधियों को जेल की सलाखों से छुड़ाने का बड़ा रैकेट चल रहा है। एक अधिवक्ता समेत पांच आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पिछले वर्ष पूर्वी व दक्षिण जोन के करीब ढाई सौ लोगों की जो सूची तैयार की थी, उसे भी विवेचना में शामिल किया है। इस सूची में अपराधी, माफिया, अधिवक्ता व जमानतदार शामिल हैं। सभी के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही पुलिस फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगा रही है। गिरफ्तार आरोपितों के फोन की काल डिटेल से अहम सुराग मिले हैं।

फर्जी जमानत मामले का पर्दाफाश पिछले वर्ष विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) के लिपिक की ओर से कोतवाली में मुकदमा लिखाने के बाद हुआ था। तत्कालीन डीआइजी डा. प्रीतिंदर सिंह ने एसआइटी का गठन किया था और विवेचना के बाद 19 जमानतदार व 82 अपराधियों के नाम सामने आए थे। ज्यादातर जमानतदार बिठूर, चौबेपुर क्षेत्रों के रहने वाले थे। उन्होंने अपने बयान में बिठूर के एक अधिवक्ता का भी नाम बताया था, जो उन्हें जमानत देने के बदले रकम देता था। हालांकि पुलिस ने पुख्ता सुबूत न होने के कारण उस अधिवक्ता को आरोपित नहीं बनाया था, लेकिन प्रकाश में आए 61 आरोपितों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था।

बुधवार को क्राइम ब्रांच ने फर्जी जमानत कराने के मामले में एक अधिवक्ता शील कुमार गुप्ता समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया तो एक नए गैंग का राजफाश हुआ। पता लगा कि ये आरोपित जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराते थे। गिरफ्त में आए औरैया के वृंदावन व सुरेंद्र ने बताया कि आरोपित कानपुर शहर ही नहीं, आसपास के अन्य जिलों में भी अपराधियों की जमानत कराते थे।

कोतवाली पुलिस बढ़ाएगी पुराने केस की जांच का दायरा - कोतवाली में पिछले वर्ष दर्ज हुए मुकदमे की जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष 101 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 61 आरोपित जेल गए थे। फरार आरोपितों की तलाश फिर से शुरू की गई है। इसी के साथ पूर्वी व दक्षिण जोन के जिन ढाई सौ लोगों की सूची बनी थी, उनके खिलाफ भी सुबूत जुटाए जा रहे हैं।

कल्याणपुर पुलिस कर रही फर्जी दस्तावेज मामले की जांच - अधिवक्ता समेत पांच आरोपितों के गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए कल्याणपुर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। यहां भी काल डिटेल व अन्य दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से सूची बनाई जा रही है। दोनों ही थानों की पुलिस की मदद क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। जो भी व्यक्ति दोषी मिलेगा, उसका नाम मुकदमे में बढ़ाकर गिरफ्तारी की जाएगी।

उरई में बाढ़ का कहर, सेना ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया शुरू

उरई । उरई के कालपी, रामपुरा और कुठौंद क्षेत्र में यमुना व सिंध नदियों का पानी लगातार तेजी से बढ़ना जारी है। हालात बिगड़े को सेना बुला ली गई, गुरुवार देर रात सेना ने रामपुरा क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया। सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे हैं जिनको निकाला जाना है। कुठौंद-औरैया हाईवे पर नदी जैसा आलम हो गया है, सड़क पर नावें चल रही हैं।

गुरुवार रात पानी का बहाव तेज होने और अंधेरे के कारण एनडीआरएफ और सेना को रेस्क्यू आपरेशन में दिक्कत हुई। शुक्रवार सुबह से ही सेना ने मोर्चा संभाल लिया और सबसे ज्यादा प्रभावित गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना ने अपनी टीमों को कुसरेपुरा, मुल्लेकापुरा, निनावली, मोहब्बतपुरा, बिहौड़, किशनपुरा आदि गांव से ग्रामीणों को रेस्क्यू कर निकालने के लिए भेजा है। सेना के जवान अपनी बोटों से पानी के सैलाब को चीरते हुए प्रभावित गांव में पहुंच गए हैं और वहां से लोगों को लाने का काम शुरू कर दिया गया। मौके पर एसडीएम सालिकराम और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। रेस्क्यू किए जा रहे ग्रामीणों को रामपुरा स्थित राजा चित्तरसिंह बालिका विद्यालय में ठहराया जायेगा। इधर औरैया-कुठौंद हाइवे पर बाढ़ का पानी आने से कुठौंद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है, जबकि कालपी में आधा दर्जन मोहल्लों में पानी आ जाने के बाद वहां पर नावें भेजकर प्रशासन ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने घरों का सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ घर खाली करने शुरू कर दिए हैं।

ऑफेंसिव मोड में काम करेगी भाजपा की आइटी सेल, कार्यशाला को सीएम योगी आदित्यनाथ भी करेंगे संबोधित

लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में इंटरनेट मीडिया का व्यापक स्तर पर प्रयोग करना चाहती है। इसी अभियान को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार को अपनी इंटरनेट मीडिया के साथ ही आईटी विभाग की टीम की बैठक कर रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जा रही इस बैठक को लेकर आइटी सेल के संयोजक कामेश्वर सिंह ने कहा कि भाजपा की आइटी सेल अब ऑफेंसिव मोड में काम करेगी। अब हम सेल की टीम के साथ कार्टून तथा कैरिकेचर के माध्यम से विपक्ष को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया टीम को बूथ लेवल तक पहुंचाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अब चुनावी रैलियां पहले जैसी नहीं होंगी। ऐसे में वर्चुअल माध्यम की उपयोगिता बढ़ी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा आइटी सेल की इस वर्कशॉप को सीएम योगी आदित्यनाथ दिन में तीन बजे से संबोधित करेंगे। उनके साथ भाजपा आइटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय भी कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इस दौरान भाजपा उत्तर प्रदेश की इंटरनेट मीडिया टीम भी मौजूद रहेगी।

भारतीय जनता पार्टी की आइटी तथा इंटरनेट मीडिया सेल की शुक्रवार को अहम बैठक है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा, भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल तथा भाजपा इंटरनेट मीडिया सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय भी भाग लेंगे। बैठक शाम को चार बजे तक चलेगी। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के सोशल मीडिया प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। लखनऊ की इस एकदिनी कार्यशाला में भाजपा आईटी व सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय विशेष रूप से उपस्थित रहकर आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के संयोजक व सहसंयोजकों का कार्ययोजना के संदर्भ में विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन करेंगे।

मेरठ में सावन शिवरात्रि उत्सव पर एक मंदिर के बाहर सुरक्षाकर्मी पहरा देते हुए।

हर ग्राम पंचायत में होंगे दो जनसेवा केन्द्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं होगी दिक्कत

लखनऊ । प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केन्द्रों तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन देने के बाद बहुत आसानी से उनके प्रमाणपत्र बन जाएंगे। साथ में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इन सुविधाओं की फीस जमा हो सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन जन सेवा केन्द्रों पर तत्काल मिलेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार यूपी में हर ग्राम पंचायत में दो जनसेवा केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 16 नवम्बर 2020 से शुरू की गई सीएससी 3.0 योजना से आज तक प्रदेश में 1,52,830 जन सेवा केन्द्र स्थापित करा दिए गए हैं। इन जनसेवा केन्द्रों में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से एकीकृत किया गया है। साथ में आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपये तय कर दिया गया है।

जन सेवा केन्द्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी वृद्धि की गई है। कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को अधिक मिला है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े केन्द्रों पर 59, 639 लोग आज तक कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से 24.50 करोड़ लोगों को मिला लाभ- सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 267 शासकीय सेवाओं को जन सुविधा केन्द्रों और सीधे इंटरनेट से जोड़ा है। इस सुविधा से राज्य सरकार की योजनाओं का 24.50 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं।

डिजी लॉकर पर 10 करोड़ से अधिक प्रमाण-पत्र कराए जा चुके उपलब्ध - डिजिटल लॉकर योजना के तहत प्रदेश में 30.84 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर खोले जा चुके हैं। प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा (आईटीआई), माध्यमिक शिक्षा (यूपी बोर्ड), प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा) द्वारा जारी मार्कशीट एवं प्रमाण-पत्रों का डिजीलॉकर से इन्टीग्रेशन भी पूरा कर लिया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में संशोधन के बाद 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। इसी के साथ कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी मुरादाबाद के खुशाबे अली की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति मो. असलम ने खुशाबे अली के अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। खुशाबे अली के खिलाफ उसकी बीवी ने आठ सितंबर 2020 को मुरादाबाद के भोजपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और धमकी देने के अलावा आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

याची के अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी का कहना था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पीड़िता ने आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने व याची के भाइयों द्वारा दुष्कर्म करने की बात से इनकार किया है। साथ ही आईपीसी की धारा 375 में वर्ष 2013 में किए गए संशोधन के बाद 15 वर्ष की आयु से अधिक की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि धारा 375 में कई संशोधन किए गए हैं। संशोधित धारा की उपधारा दो में यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने याची की जमानत मंजूर करते हुए शर्तों के साथ उसे रिहा करने का ?आदेश दिया है।

11 अगस्त को चीन से भारत लाया जाएगा अमन नागसेन का शव, परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक सतीश कुमार दास

गया । गया के छात्र अमन का पार्विश शरीर चीन से 11 अगस्त को गया लाए जाने की संभावना है। इसके लिए तैयारी हो रही है। गुरुवार को डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि चीन में अमन की हत्या और उसे भारत लाने की प्रकिया के संबंध में अरविंद कुमार, मिनिस्टर काउंसिल इंडियन एंबेसी, बीजिंग ने उनसे बात की है। उन्होंने बताया कि वे लगातार परिवार के संपर्क में हैं। स्थानीय आयुक्त दिल्ली को भी इस संबंध में सभी प्रकार की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। मालूम हो कि चीन में रहकर पढ़ाई करने वाले गया निवासी छात्र की चीन में हत्या कर दी गई है। अब उसके शव को भारत लाने की मुहिम चल रही है।

हत्या का दर्ज हुआ है मामला- बताया गया कि अमन की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में एक विदेशी आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में इंडियन एंबेसी, बीजिंग फॉलोअप कर रहा है। जिससे दिवंगत छात्र के परिवार को न्याय मिल सके। मामला चीन की सरकार से संबंधित है, इसलिए इंडियन एंबेसी बीजिंग, चीन की सरकार के साथ मामले में फॉलोअप कर रहे हैं।

छात्र का पोस्टमार्टम किया गया है। गुरुवार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद शव को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। डीएम ने बताया कि विदेश मंत्रालय के वरीय पदाधिकारी ने मृतक के परिवार वालों से बात की है। प्रक्रिया से परिवार को अवगत कराया गया है। मखदूमपुर विधायक सतीश कुमार दास गुरुवार दोपहर अंबेडकरनगर में नागसेन अमन के आवास पर पहुंचे। वहां परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया और परिजनों को धैर्य दिलाते हुये कहा कि वह केंद्र सरकार व अपने दल के नेता तेजस्वी यादव से इस मुददे पर बात कर शीघ्र ही अमन के पार्थिव शरीर को गया लाने का प्रयास करेंगें। इस दौरान अमन के पिता उदय पासवान व उसके चाचा राजकिशोर पासवान, माता रीता कुमारी व बहन ज्योत्सना को जब भी कोई संतावना देने पहुंच रहा है

बिहार में अपराध बेलगाम: बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया को गोलियों से भूना, समर्थकों ने सड़क पर जलाए टायर

सरायरंजन । समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना के बखरी गांव में अपराधियों ने उदा पंचायत के पूर्व मुखिया व वर्तमान में उप मुखिया शशि झा की गोलियों से भून कर हत्या कर दी। अपराधियों ने इस घटना को सुबह करीब 10 बजे उस समय अंजाम दिया जब उप मुखिया एक पंचायत के बाद घर लौटने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे। इस घटना से मुसरीघरारी इलाके में दहशत के साथ ही तनाव उत्पन्न हो गया है।

मुसरीघरारी चौक की सभी दुकानें बंद हो गई है वहीं उप मुखिया के समर्थक सड़क पर टायर जला रोष जता रहे है जिससे आवमगमन बाधित हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में शशि झा की पत्नी पंचायत की मुखिया है। बताया गया है कि पंचायत के बखरी गांव में मारपीट की एक घटना को लेकर बुलाई गई पंचायत में शामिल होने के लिए उप मुखिया शशि झा गए थे।

पंचायत समाप्त होने के बाद झा अपनी फार्च्यूनर कार में बैठे और उसे जैसे ही स्टार्ट किया, एक व्यक्ति ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। इसी दौरान दो बदमाश पहुंचे और गाड़ी की खिड़की से मुखिया पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली उप मुखिया के चेहरे पर लगी। उसके अलावा अन्य गोली सिर और सीने में लगी जिससे घटनास्थल पर ही मुखिया की मौत हो गई। बताया गया है कि उप मुखिया के सिर में ही आधा दर्जन से अधिक गोली लगी है।

मुखिया की हत्या की जानकारी मिलने पर परिजन और समर्थक घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को घर ले गए। खबर लिखे जाने तक उप मुखिया की लाश घर पर ही थी जबकि पुलिस नहीं पहुंची थी। हालांकि मुसरीघरारी में समर्थको के रोष को देखते हुए जगह-जगह पुलिस तैनात की गई है।

बंटवारे की रंजिश में चाचा-भतीजे की स्कार्पियों से कुचलकर हत्या

बदायूं । में लग्जरी गाड़ी से टक्कर मारकर गुरुवार शाम बाइक सवार चाचा भतीजे की हत्या कर दी गसी। घटना के पीछे संपत्ति बंटवारे की रंजिश बतायी जा रही है। मृतक के भाई ने इस मामले में विरोधी पक्ष के सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वारदात में प्रयुक्त स्कार्पियों पुलिस ने बरामद कर ली है। वही दो नामजद हिरासत में ले लिये गये हैं। शवों को पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है।

दोहरे हत्याकांड की यह सनसनीखेज वारदात इस्लामनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम बिसौली रोड पर हुई। इस्लामनगर के ही गांव अल्हीपुर चिचेटा निवासी पूर्व फौजी आर्येन्द्र सिंह अपनी बाइक से रिश्ते के भतीजे गौरव के साथ इस्लामनगर की ओर जाने को निकले थे। मुकदमे के मुताबिक रास्ते में गांव कंधरपुर व लभारी के बीच विपरीत दिशा से स्कार्पियों में सवार होकर आ रहे विरोधी पक्ष के सुभाष, रामभान, आशीष, विनय, प्रेमपाल, सुरेंद्र व नरेंद्र ने एक राय होकर आर्येन्द्र की बाइक रांग साइड पर आकर टक्कर मार दी। गाड़ी सुभाष चला रहा था। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए और यहां हालत गंभीर देख कर दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

परिवार के लोग दोनों को बरेली ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के पीछे मछली के तालाब के बंटवारे को लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आनन-फानन में गाड़ी बरामद करने के साथ ही दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि बाकी के नामजदों की तलाश चल रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है। शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिवार वालों को सौंपा जायेगा।

पुलिस मुख्यालय का दावा: बिहार की बदली तस्वीर, 2005 के मुकाबले घटी अपहरण दर, इन अपराधों में भी आई कमी

पटना । बिहार में अपराध वृद्धि के आरोपों पर पुलिस मुख्यालय ने आंकड़ों के साथ दावा किया है कि साल 2005 के मुकाबले अपराध दर में कमी आई है। हत्या और फिरौती हेतु अपहरण के मामले समेत अधिकांश अपराध दर घटी है। अपराध दर का निर्धारण प्रति एक लाख की जनसंख्या पर घटित घटनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। हर साल राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं।

फिरौती के लिए जून तक हुई 24 घटनाएं

पुलिस मुख्यालय के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से जून तक फिरौती हेतु अपहरण के 23 कांड सामने आए। इनमें 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अगवा किए गए 24 लोगों में 23 को बरामद कर लिया गया। वर्ष 2019 में 0.036 अपराध दर के साथ फिरौती हेतु अपहरण में बिहार 13 वें स्थान पर है। वहीं 2005 में फिरौती हेतु अपहरण के 251 कांड दर्ज किए गए थे। इस शीर्ष में 2005 में बिहार का अपराध दर 0.279 था जो वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 8 गुणा अधिक था।

हत्या का औसत 7.72 रहा- पुलिस मुख्यालय के मुताबिक वर्ष 2021 में जून तक हत्या की घटनाओं का औसत 7.72 रहा। वर्ष 2019 में हत्या के शीर्ष में राष्ट्रीय औसत दर 2.2 है। हत्या के मामले में वर्ष 2015 से 2019 के दौरान बिहार का स्थान 9वें से 17वें के बीच रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2005 में हत्या की घटनाओं में बिहार का अपराध दर 3.9 के आधार पर देश में 9 वें स्थान पर था। वहीं 2019 में बिहार में हत्या का अपराध दर 2.6 रहा।

चोरी में बिहार का 13वां स्थान- एनसीआरबी के वर्ष 2019 के आंकड़ों का हवाला देते हुए पुलिस मुख्यालय ने कहा कि चोरी के मामलों में राष्ट्रीय औसत अपराध दर 50.5 है। इसी वर्ष में चोरी की घटनाओं में बिहार का अपराध दर 29.1 रहा जो कि देश में 13वां स्थान है। वर्ष 2003 में बिहार में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 1134023 थी। वहीं वर्ष 2019-2020 में राज्य में 1360714 वाहनों का पंजीयन हुआ। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि वाहन की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की वजह से गाड़ियों की चोरी की संख्या में वृद्धि स्वाभाविक है।

महंगाई- भ्रष्टाचार के खिलाफ ताजनगरी की गली-गली में घूमेंगी समाजवादी साइकिल

आगरा । आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सक्रियता बढ़ा दी है।छोटे लोहिया यानि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने समाजवादी साइकिल यात्राएं निकालीं। अब ये यात्राएं गली-गली निकाली जाएंगी। इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न आदि मुद्दों को उठाया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार की उपलब्धियों और सपा की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा।

महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने कहा कि महंगाई आसमान पर है। पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भाजपा सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। न व्यापारी सुरक्षित है और न ही आम आदमी। जनता भाजपा सरकार से परेशान हो गई है। ऐसे में लोग अब सपा से उम्मीद लगा रहे हैं। सपा भी लोगों की आवाज को उठाने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। अब जल्द ही गली-गली भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसके लिए साइकिल यात्राएं निकाली जाएंगी। जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लोगों को सपा सरकार में हुए कार्यों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि भाजपा सरकार किस तरह से लोगों को गुमराह कर रही है।उसने जनता से जो वादे किए थे, उस पर वह खरी नहीं उतरी है। जबकि सपा सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया।

कार्यशाला में सीएम ने कहा

सहकारिता हमारे संस्कारों और संस्कृति में शामिल

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता हमारे संस्कारों एवं संस्कृति में शामिल है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा वसुधैव कु टंबकम के मार्ग पर चलते हैं। सबके लाभ, सबके कल्याण और सबकी भलाई की सोच ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि मप्र ने कोविड काल में सहकारिता के माध्यम से आपदा नियंत्रण का आदर्श प्रस्तुत किया। जिला, ब्लॉक, वार्ड एवं ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों ने कोरोना नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को मंत्रालय में मप्र में सहकारिता आंदोलन नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए क्षितिज विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के सहकारिता विशेषज्ञ भी शामिल हुए। चौहान ने कहा कि मप्र में महिला स्व-सहायता समूहों ने सहकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य मंत्रालय में सहकारिता आंदोलन नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए क्षितिज विषय पर मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद थे।

किया है। प्रदेश में इन्हें सशक्त बनाने के लिए 1400 करोड़ रूपए का बैंक ऋण चार फीसदी ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। चौहान ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था का नवनिर्माण किया जाएगा।

पर्यटन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य-पालन आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत बनाया जाएगा। प्रदेश में सहकारिता ग्रोथ का इंजन बनेगी। उन्होंने कहा कि मप्र में फसलों का बंपर उत्पादन है। यहां देश में सर्वाधिक गेहूं होता है। उद्यानिकी फसलों का भी बहुत उत्पादन है। प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। चौहान ने अमूल के निदेशक सोडी से कहा कि अमूल की कमाल की मार्केटिंग है। अमूल दूध पीता है इंडिया, गीत मेरी जुबान पर भी है। कार्यशाला में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, वाशिंगटन डीसी की सहकारिता विशेषज्ञ प्रो. शशिका रवि सहित अन्य विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

नरोत्तम जी हमारे, उनका भी करना पड़ा रेस्क्यू

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को बाढ़ प्रभावितों से मिलने के दौरान बाढ़ में फंसने और फिर उन्हें एयरलिफ्ट किए जाने का मामला शुक्रवार को कैबिनेट में भी छाया रहा। कैबिनेट के दौरान जब मुख्यमंत्री मंत्रियों की उनकी सक्रियता के लिए तारीफ कर रहे थे, तब उन्होंने गृह मंत्री का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी हमारे....।

कैबिनेट में छाया गृह मंत्री के रेस्क्यू का मामला

वे भी लोगों की मदद करते- करते बाढ़ में फंस गए। उनका खुद रेस्क्यू करना पड़ा। लोगों को बचाने वह पानी में उतर पड़े। ऐसा जज्बा ही हमें लोगों से जोड़ता है। अन्य मंत्रियों ने भी गृह मंत्री के इस जज्बे की तारीफ की तो गृह मंत्री मिश्रा ने हाथ जोड़ लिए। यहां बता दें कि दतिया जिले के एक गांव में बाढ़ प्रभावितों से मिलने नाव से जाते हुए पहले तो उनकी नाव ही पंचर हो गई। जैसे - तैसे वे पैदल चलकर प्रभावितों के बीच पहुंचें। यहां सभी बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। उसके बाद गृह मंत्री को एयरलिफ्ट किया गया। उनका एयरलिफ्ट करने वाला फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पिछले तीन दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने किया सुषमा स्वराज को नमन

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश से सांसद रहीं स्व. सुषमा स्वराज को उनकी दूसरी पुण्य-तिथि पर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास के सभाकक्ष में स्वर्गीय सुषमा स्वराज के चित्र पर पुष्प माला अर्पित की। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी उपस्थित थे।

शिवराज ने मोदी के निर्णय का किया स्वागत

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया है। श्री चौहान ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि 'हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपने अद्भुत खेल से न सिर्फ सारी दुनिया का दिल जीता, बल्कि अपने देश को भी एक अलग पहचान दिलाई। खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची आदरांजलि है। इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं।' प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी श्री मोदी के इस निर्णय का स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा के नेताओं और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने श्री मोदी के निर्णय के समर्थन में ट्वीट किए हैं।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल कमलनाथ के निवास पर

भोपाल । प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भोपाल स्थित निवास 9, श्यामला हिल्स पर रविवार, 8 अगस्त को शाम 7 बजे आहूत की गई है। उक्त आशय की जानकारी प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री प्रशासन प्रभारी राजीव सिंह ने दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज कटनी प्रवास पर

भोपाल । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा शनिवार, 7 अगस्त को कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विष्णुदत्त शर्मा 7 अगस्त को कटनी पहुंचकर सुबह 10 बजे बहोरीबंद विधानसभा के ग्राम तेवरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात् कटनी पहुंचकर दोपहर 2.30 बजे कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में भाग लेंगे। शाम 4 बजे श्री शर्मा पार्टी के जिला कार्यालय में जिला पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों की बैठक में उपस्थित रहेंगे। कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट कर शाम 5 बजे एनकेजे थाना कटनी के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे।

खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद करना जनता को गौरवान्वित करने वाला: शर्मा

भोपाल । खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर किए जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने विश्व पटल पर भारत को कई बार गौरवांवित किया है।

राष्ट्रीय आपदा कोष से सहायता की नितांत आवश्यकता

मप्र ने नुकसान के सर्वे के लिए केंद्रीय दल भेजने लिखा पत्र

भोपाल (एजेंसी)। राज्य शासन ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में विशेष तौर पर ग्वालियर, चम्बल संभाग के 8 जिलों में अभूतपूर्व भारी वर्षा से हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार से तुरंत अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है। राज्य शासन द्वारा विस्तृत ज्ञापन सौंपने के लिए मैदानी सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि केंद्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के मूल्यांकन से प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी, जिसकी नितांत आवश्यकता है।

राज्य शासन द्वारा विस्तृत ज्ञापन सौंपने के लिए मैदानी सर्वेक्षण कर एकत्र किए जा रहे हैं आंकड़े

पत्र में जानकारी दी गई है कि ग्वालियर और चम्बल संभाग में बहुत ही कम समय में हुई मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। भारी वर्षा के चलते चम्बल, सिंध, पार्वती, कूनो, सीप और क्वारी नदियों का जल स्तर भी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बाढ़ के कारण श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड जिले की बहुत सी बस्तियों और गांवों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्र शासन को भेजे पत्र में लिखा गया है कि एक अप्रैल 2021 को राज्य आपदा राहत कोष का खर्च शून्य था। राज्य आपदा राहत कोष 2020-21 के तहत 2427 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से 20 प्रतिशत यानि 485.4 करोड़ रुपए मिटिगेशन शमन और 970.80 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए निर्धारित किए गए।

एक अप्रैल, 2021 से 5 अगस्त के मध्य एसडीआरएफके तहत 576.13 करोड़ रुपए व्यय होने के बाद शेष राशि 1364.47 करोड़ रुपए है। कोविड संक्रमण की भावी संभावना को देखते हुए यह राशि बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। अतएव एनडीआरएफसे अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। प्रदेश में वर्षा की जानकारी देते हुए कहा गया कि मप्र में आज दिनांक तक औसत वर्षा 503.2 मिमी होनी चाहिए, जिसके विरुद्ध 12 प्रतिशत अधिक 562ण्7 मिमी वर्षा हो चुकी है। पत्र में बाढ़ प्रभावित जिलों में हुई बारिश का भी ब्यौरा दिया गया है।

आज मप्र का अन्न उत्सव देखेंगे दूसरे राज्यों के मंत्री व अफसर

पीएम नरेंद्र मोदी भी वीसी के माध्यम से करेंगे हितग्राहियों से संवाद

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शनिवार, 7 अगस्त को प्रदेश में आयोजित होने वाला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम राज्य शासन का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को वीसी के माध्यम से संबोधित करेंगे। साथ ही हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। अन्य राज्यों के मंत्री एवं अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मप्र आ रहे हैं। जिस प्रकार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों द्वारा कोरोना प्रबंधन और प्रदेश का टीकाकरण अभियान पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, उसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 7 जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया एवं गुना को छोड़कर शेष प्रदेश में यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित होगा। चौहान ने कहा कि शनिवार को प्रदेश की समस्त 25 हजार 435 उचित मूल्य दुकानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर पहले दिन 100 हितग्राहियों को थैले में निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। उसके बाद शेष हितग्राहियों को निःशुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा।

चौहान ने बताया कि शनिवार को सुबह 10 बजे आरंभ होने वाले इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपस्थित हितग्राहियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन-सामान्य को कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कार्यक्रम की तैयारी एवं आयोजन की व्यवस्था देखेंगे।

भाजपा के अन्न उत्सव पर कमलनाथ ने उठाए सवाल

भोपाल (एजेंसी)। भाजपा द्वारा देशभर में शनिवार, 7 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्न उत्सव की तैयारी के बीच प्रदेश कांगेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं।

नाथ ने कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग सहित कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, 1250 से अधिक गांव अभी भी इस भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आज पूरा देश हमारे प्रदेश में आई इस भीषण बाढ़ से चिंतित है और खुद को संवेदनशील बताने वाली प्रदेश सरकार प्रदेश में शनिवार को भव्य तरीके से अन्य महोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटी है, राशन दुकानो को होर्डिंग- पोस्टर लगाकर सजाया जा रहा है, अभी आवश्यकता है बाढ़ में फंसे हजारों लोगों के जीवन को बचाने की, राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने की, लोगों के रहने, खाने-पीने की व्यवस्था करने की, लोगों के स्वास्थ्य की, आधारभूत संरचनाओं के पुनर्निर्माण की। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने 70 साल में ऐसी विभीषिका नहीं देखी, यह महाविनाश है, हजारों करोड़ रुपए की आधारभूत संरचनाएं नष्ट हो चुकी है। एक तरफ वह कह रहे हैं कि मैं दिल्ली संसदीय बोर्ड की बैठक छोड़कर चला आया, मैंने अपने सभी कार्यक्रम बैठक तक निरस्त कर दी, क्योंकि मुझे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करना है और दूसरी तरफ शनिवार को प्रदेश में भव्य तरीके से मनाने वाला यह उत्सव सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर कर रहा है। नाथ ने कटाक्ष किया कि इस अन्न उत्सव के बहाने भाजपा का प्रचार-प्रसार व ब्रांडिंग का काम किया जा रहा है, राशन के बैग पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के फोटो लगाकर करोड़ों खर्च कर खुद का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, सरकार चाहती तो बगैर किसी कार्यक्रम के भी सादगी से गरीबों में राशन वितरित कर, करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची को रोक सकती थी।

21 से 30 सितंबर तक होगी साइबर इंवेस्टीगेशन एंड इन्टेलिजेन्स समिट

भोपाल । मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी साइबर क्राइम के अनुसंधान, आसूचना संकलन तथा साइबर सुरक्षा क्षेत्र में एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। 21 से 30 सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को ऑनलाईन माध्यम से आयोजित कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस समिट का उददेश्य है कि पुलिस तथा लॉ-एनफोर्समेन्ट क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थानों के प्रतिभागियों के साइबर क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास में मध्यप्रदेश पुलिस की ओर से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देकर एक मिसाल कायम की जा सके। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हजार प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। यह दस दिवसीय कार्यक्रम प्रतिदिन लाइव स्ट्रीमिंग माध्यम से संचालित होगा तथा मध्यप्रदेश के पुलिस अधिकारी, प्रशिक्षु अधिकारी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों के साथ इसका लाभ प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक पीएचक्यू विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) अरूणा मोहन राव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) अनुराधा शंकर सिंह, निदेशक (पुलिस अकादमी भौंरी) राजेश चावला, उपनिदेशक (पुलिस अकादमी भौंरी) विनीत कपूर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर सेल) योगेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भोपाल जोन) ए.साई मनोहर, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवर्ता) राकेश गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) अशोक गोयल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) मलय जैन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) इरमीन शाह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पुलिस अकादमी भौंरी) रश्मि पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पुलिस अकादमी भौंरी) नीरज पांडे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

मध्य प्रदेश की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार: गुप्ता

भोपाल (एजेंसी)। ग्वालियर-चंबल संभाग और बुंदेलखंड के कुछ हिस्से में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने की है।

गुप्ता ने कहा कि बहुत से इलाकों में तीन से चार दिन से लोगों को सहायता नहीं मिली है। लोग भूख-प्यास से तड़प रहे हैं। जबकि बाढ़ से लोगों का जीवन बेहाल हो गया है, तब मुख्यमंत्री ट्वीट करके बता रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर ली है और उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है। कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना चाहती है। आपने पीएम से बातचीत में इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की या नहीं। अगर आपने मांग नहीं की है तो क्या आप इसे राष्ट्रीय आपदा नहीं मानते, कांग्रेस मांग करती है कि बाढ़ को तुरंत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। बाढ़ प्रभावित लोगों को पिछले तीन से चार दिन तक कोई सहायता नहीं मिली, वे भूख-प्यास से तड़पते रहे। भूख-प्यास और बरबादी से नाराज लोगों की नाराजगी के चलते खुद आपको अपना श्योपुर दौरा रद्द करना पड़ा।

छिंदवाड़ा और खरगोन में अन्नोत्सव की तैयारियों की समीक्षा

हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण राशन का वितरण हो सुनिश्चित : पटेल

भोपाल (एजेंसी)। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास एवं छिंदवाड़ा और खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दोनों जिलों के अधिकारियों से अलग-अलग समय में 7 अगस्त को प्रदेश के साथ जिलों में मनाए जाने वाले अन्न उत्सव की तैयारियों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के सभी पात्र परिवारों को नियमित राशन के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मिलने वाले राशन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मंत्री श्री पटेल ने दोनो जिलों के अधिकारियों से अन्न उत्सव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी और सभी नोडल अधिकारी निगरानी समितियों के माध्यम से प्रत्येक उचित मूल्य दुकान से गुणवत्तापूर्ण राशन का ही वितरण कराया जाना सुनिश्चित कराएं। लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रत्येक जरूरतमंद और पात्र परिवार को पात्रतानुरूप शत-प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन वितरण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन टीम की सराहना की और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

भाजपा के स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कल

भोपाल (एजेंसी)। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत मध्यप्रदेश में 8 अगस्त को होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी तरूण चुघ एवं प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा जिला स्तरीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे।

स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय महासचिव चुघ एवं प्रदेश अध्यक्ष शर्मा

पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के प्रदेश संयोजक सरतेन्दु तिवारी ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भाजपा ने देश के 2 लाख गांवों में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की है। मध्यप्रदेश में इस अभियान के अंतर्गत जिला मंडल, ग्राम केंद्र, नगर केंद्र और बूथ स्तर तक प्रशिक्षित स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत 8 अगस्त को जिला स्तरीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण प्रदेश कार्यालय पं दीनदयाल परिसर में किया जा रहा है, जिसमें सभी 57 संगठनात्मक जिलों के स्वास्थ्य स्वयंसेवक भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा, जिसका शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी तरूण चुघ एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा करेंगे। प्रत्येक जिले से 4 सदस्य इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे, जिनमें 1 डॉक्टर, 1 महिला एवं 2 कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में शामिल होंगे।सरतेन्दु तिवारी ने बताया कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार ने जो तैयारियां की है उनमें भाजपा द्वारा प्रशिक्षित स्वास्थ्य स्वयंसेवक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे।

अन्न उत्सव दिवस आज: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम पर विशेष

पीएम ने देश के बड़े वर्ग के बारे में सोचा और उसे जमीन पर उतारा

भोपाल (एजेंसी)।

फादर डे, मदर डे, टीचर डे ऐसे ही न जाने कितने डे। डे यानी दिवसों के बारे में हमने सुना है और मनाया भी है और मनाते भी हैं। यह कल्चर और यह परंपरा हमारी नहीं है और शायद हमें जरूरत भी नहीं है। परंतु पिज्जा बर्गर के इस दौर में हमें और हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा और जो सोचा उसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में जमीन पर उतारा भी। हर गरीब हितग्राही को निःशुल्क राशन वितरण के आयोजन के पीछे सरकार की मंशा यही है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के हर उस व्यक्ति को मिले, जो इसका वास्तविक हकदार है। नागरिकों को जीवन यापन की प्रमुख जरूरतें मुहैया कराने के लिए शासन सदैव प्रयत्नशील है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जन हितैषी आयोजन के लिए स्वयं वर्चुअली हितग्राहियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप कोरोना काल में हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उदेश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी हितग्राहियों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं /चावल वितरित किया जा रहा है। इस दिन दस किलो की क्षमता वाली थैली में सबको भोजन, पर्याप्त पोषण की कल्पना के साथ राशन वितरित किया जा रहा है। 7 अगस्त को आयोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए सरकार प्रदेश की 25 हजार 435 उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क राशन वितरित कर रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के बाहर रहने वाले पात्र हितग्राही भी ले सकेंगे।

हमारे देश का इतिहास गवाह है जब भी देश पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या संकट आया सरकार ने अपने नागरिकों के लिए खुले दिल और दिमाग से योजना बनाकर आमजन की मदद के लिए अपने खजाने खोल दिए। देश ही नहीं सारी दुनिया में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जनता से आग्रह स्वरूप कहे गए तीन वाक्य 1.घर पर रहें 2. घर पर ही रहें 3. सिर्फ घर पर ही रहें, का असर यह रहा कि आम आदमी अपने काम-धंधा छोड़कर अपने घर में ही रहकर कोरोना की जंग में शामिल हो गया। एक आम आदमी जो प्रतिदिन कमाता खाता था, बिना पैसे के कितने दिन घर में रह सकता था। उसके और उसके परिवार के सामने भोजन की चुनौती सामने आ खड़ी हुई। सरकार ने कोरोना से लड़ते हुए इस जिम्मेदारी को भी निभाते हुए गरीब परिवारों को राशन उनके घर तक निःशुल्क पहुंचाने की महती भूमिका निभाई। कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क राशन माह नवंबर तक वितरित किया जाएगा। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के रूप में मैं यह कह सकता हूं कि अन्न दिवस पर हम प्रदेश के 4 करोड़ 83 लाख हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से खाद्य सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे। प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2020 से अभी तक 45 लाख नए हितग्राहियों को निःशुल्क राशन के लिए पात्रता पर्ची जारी की गई है। वर्ष 2014 से प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से बैगा, भारिया, सहरिया जैसे पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों को प्राथमिकता से खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। कोई भी पात्र हितग्राही बचा न रहे, इसके लिए 28 श्रेणियां बनाकर हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक विस्तार से 90 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय भार केंद्र सरकार वहन करेगी। बंपर गेहूं उपार्जन से प्रदेश में खाद्यान्न की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के संपन्न राज्यों की श्रेणी में आता है। पिछले साल प्रथम स्थान पर रहने के बाद पंजाब के बाद मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। पोर्टेबिलिटी के जरिए प्रदेश के 4 लाख परिवारो को राशन वितरण किया गया है। इसके अलावा नॉमिनी के जरिए 50 हजार परिवारों द्वारा राशन प्राप्त किया गया। 24 हजार 500 उचित मूल्य दुकानों से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरित किया गया। राशन वितरण में पारदर्शिता के चलते शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर हितग्राही की सूची प्रदर्शित लगवाई गई।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के प्रथम चरण में माह अप्रैल से नवंबर 2020 तक पात्र परिवारों को एक किलोग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार के मान से निःशुल्क दलिया वितरण बाजार दर से किया जाना भी विचाराधीन है। कोरोना काल में ऐसे जरूरतमंद परिवार, जिनको राशन प्राप्त नहीं हो रहा था, से घोषणा पत्र के माध्यम से 4 लाख 50 हजार हितग्राहियों को आधार कार्ड के माध्यम से अस्थाई पर्ची वितरित की गई। इन हितग्राहियों को 3 से 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माह मई से नवंबर 2021 तक निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा।

■ **लेखक प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं**

दुल्हन का लिबास पहने नजर आईं रानी चटर्जी

भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस रानी चटर्जी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। रानी चटर्जी की तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती है। वही इन दिनों रानी चटर्जी की कुछ तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन तस्वीरों में रानी चटर्जी दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। वह लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस में नजर आ रही हैं। रानी की इन तस्वीरों को देखकर फैंस उनसे शादी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बधाई हो मैम, सगाई हो रही है ना आपकी। दूसरे ने लिखा, हो गई शादी। वही कई यूजर्स कमेंट कर रानी की खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों ही रानी चटर्जी का बॉयफ्रेंड मनदीप से ब्रेकअप हुआ है। रानी के घर में उनकी शादी को लेकर तैयारी चल रही थी। लेकिन, ब्रेकअप की खबरों ने सभी का दिल तोड़ दिया था।

राजपाल यादव ने किया खुलासा

कि टाइपकास्ट होने से बचने के लिए वह क्या करते हैं

फिल्म उद्योग में 24 साल से सक्रिय राजपाल यादव का कहना है कि उन्होंने अब तक जो हासिल किया है, उससे वह खुश हैं। हालांकि, यह प्रतिभाशाली अभिनेता, यादातर अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ दिया है और टाइपकास्ट होने से बचने की कोशिश की है। राजपाल यादव ने बताया, मैंने आज तक जो किया है उससे मैं बहुत खुश हूं। पहले दिन से ही मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने द्वारा निभाए गए किरदार को कभी नहीं दोहराऊंगा। अभिनेता बहुत जल्दी टाइपकास्ट हो जाते हैं। इसलिए भले ही मुझे इसी तरह की भूमिका की पेशकश की गई हो। लेकिन मैं इसकी मानसिकता बदलता हूं। एक अभिनेता अपनी काया नहीं बदल सकता, लेकिन मानसिकता बदली जा सकती है। अभिनेता ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ने के लिए क्या किया। उन्होंने आगे जोड़ा कि, मैंने निगेटिव से लेकर कॉमेडी से लेकर लीड और सपोर्टिंग तक हर संभव तरह की भूमिकाएं की हैं। कुछ लोग कहते हैं, एक बार मुख्य भूमिका निभाने के बाद आपको सहायक किरदार नहीं निभाने चाहिए। लेकिन मैंने वह किया है और मुझे इन सिद्धांतों को तोड़ने में मजा आता है। उन्होंने पर्दे पर जिस तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, उनमें राजपाल को हास्य के लिए जाना जाता है। उनके लिए कॉमिक भूमिका निभाना कितना आसान या मुश्किल है? अभिनेता ने कहा, कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आपका निर्देशक अच्छा है, तो अभिनेता के लिए काम और भी आसान हो जाता है। अगर आप किसी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं और अपने निर्देशक के साथ ठीक से संवाद करने में असमर्थ हैं, तो यह स्क्रीन पर भी दर्शाता है। फिल्मों की बात करें तो, अभिनेता की नवीनतम प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित डिजिटल रूप से रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 है। राजपाल ने पहले फिल्म निर्माता के साथ भूल भुलैया, हंगामा, भागम भाग और अन्य जैसी प्रफुल्लित करने वाली फिल्मों में सहयोग किया है।

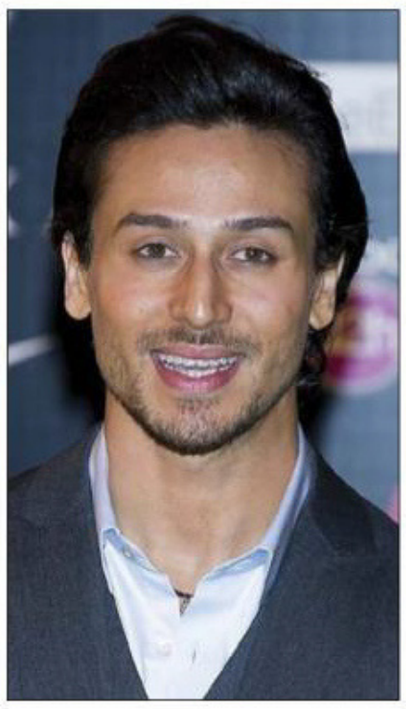

सोशल मीडिया ट्रोलर्स के लिए टाइगर श्रॉफ का मैसेज

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपनी शुरुआत करने के बाद से अपने लुक्स, अभिनय कौशल और अन्य चीजों के लिए कई आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। अभिनेता का कहना है कि जब तक उन्हें.. सोशल मीडिया पर नफरत से यादा प्यार मिलता रहता है, वह यादातर ट्रोलर्स से अप्रभावित रहते हैं। हाल ही में अभिनेता ने अरबाज खान के साथ चैट शो पिंच सीजन 2 हिस्सा लिया था। जैसा कि शो का विषय सेलिब्रिटी गेस्ट के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल और बेकार के टिप्पणियों के बारे में बात करना है। टाइगर ने टिप्पणियों को पढ़ा, जिसमें यादातर उनके दिखने और उनके अभिनय कौशल के लिए उन्हें ट्रोल किया गया है। अपने सभी ट्रोल्स को जवाब देते हुए टाइगर ने कहा, मुझे पता है कि जब से मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब से लोगों ने ये लड़का है या लड़की कहा था, लोगों ने मेरे चेहरे पर कमेंट किया और कहा कि मैं एक लड़की की तरह दिखता हूं। और फिर वे मेरे शरीर को देखते हैं! लोगों का एक वर्ग मुझे मेरे एक्शन दृश्यों आदि के लिए प्यार करता है। जब तक मेरे प्रशंसकों से मेरे लिए प्यार आ रहा है, मैं ठीक हूं। मैंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने का फैसला किया है, मैंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना है। जब आप कोशिश करते हैं और अपना खुद का कुछ बनाते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह लेता हूं। उन्होंने यह भी कहा, जब ट्रोलिंग की बात आती है, तो यह कई बार डरावना होता है। अरबाज खान की पिंच सीजन 2 का एपिसोड 3 अगस्त को रिलीज हो रहा है।

करण जौहर ने बताया किस चीज से डरते हैं सबसे यादा

फिल्ममेकर करण जौहर जल्द ही बिग बॉस ओटीटी को होस्ट करते नजर आने वाले हैं। करण इससे पहले भी कई शोज को होस्ट करते दिख चुके हैं। हाल ही में करण जौहर ने अपने सबसे बड़े डर का खुलासा किया है। करण एक सफल फिल्ममेकर होने के अलावा एक अछे पिता भी हैं। वह हमेशा ही अपने दोनों बचों रूही और यश के साथ वक्त बिताते दिखाई देते हैं। करण अपने बचों से बेहद प्यार करते हैं और उनसे अलग रहना करण के लिए सबसे डरावना है। जब एक इंटरव्यू के दौरान करण जौहर से पूछा गया कि वो किस बात से सबसे यादा डरते हैं। इस पर उन्होंने कहा, उनका सबसे बड़ा डर ही यह है कि वह किसी भी वजह से अपने बचों से दूर न हो जाए। उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा फोमो अपने बचों से दूर होने का है। मेरी खुशियां ही उनकी वजह से है और इसीलिए मैं उनसे यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। बता दें कि करण 2017 में सेरोगेसी के जरिए जुड़वा बचों के पिता बने थे। लॉकडाउन के दौरान करण जौहर ने अपना पूरा वक्त अपने बचों के संग बिताया। वह अपने बचों संग सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं।

उपलब्धि- इटली के लग्जरी ब्रांड

बलगैरी की ब्रांड एंबेसडर बनीं प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय जोड़ लिया है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय जोड़ लिया है। अपने अभिनय और अपने स्टाइल से लोगों का दिल जीतने वाली प्रियंका इटली की लग्जरी ब्रांड बलगैरी की ब्रांड एंबेसडर चुनी गई हैं। कंपनी का कहना है कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ ही दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाई वैलरी का सपोर्ट करेंगी। मालूम हो कि लग्जरी ब्रांड बुलगैरी को वैलरी, जेम्स, घड़ियों और परफ्यूम के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कंपनी लेदर का सामान भी बनाती है। मैं इस बात से बेहद उत्साहित हूं कि प्रियंका हमारे परिवार में शामिल हो रही हैं। मुझे भरोसा है कि हम एक साथ महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव के साथ कई प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। वहीं, इस मामले में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि वो लग्जरी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की उम्मीद कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर के तौर पर बुलगैरी के परिवार में शामिल होने पर मुझे गर्व है। जिस गर्मजोशी के साथ टीम ने स्वागत किया है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसी कई चीजें हैं जो इस प्रतिष्ठित ब्रांड की ओर मुझे आकर्षित करती हैं।

पूजा ने बताया सर्कस की शूटिंग का अनुभव

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के पास इस समय कई प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। वह रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में रणवीर सिंह के साथ भी नजर आने वाली हैं। हाल ही में पूजा ने रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के साथ शूटिंग के अपने अनुभव के बारे में बात की। एक इंटरव्यू के दौरान पूजा हेगड़े ने कहा, फिल्म की शूटिंग में बहुत मज़ा आया। सर्कस रोहित सर और वीर (रणवीर सिंह) का तीसरा सहयोग है और उनके बीच पहले से ही वह बॉन्डिंग है। जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपको मज़ा आएगा ही। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगा जैसे हमने एक पार्टी की थी और बीच में, हम फिल्म की शूटिंग के लिए जाते थे। जब आप ऑफ-स्क्रीन इतना मज़ा करते हैं, तो मेरा मानना है कि यह स्क्रीन पर भी दिखता है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। पूजा ने हाल ही में प्रभास के साथ अपनी पैन-इंडिया फिल्म राधे श्याम की शूटिंग पूरी की है और सर्कस के साथ-साथ उनके पास सलमान खान के साथ भाईजान भी हैं। इसके अलावा वह चिरंजीवी और राम चरण के साथ आचार्य, मोस्ट एलिजिबल बैचलर में भी नजर आएंगी।

गौहर खान ने एंटरटेनमेंट इंड्रस्टीज में पूरे किए 19 साल

मॉडल से अभिनेत्री बनी गौहर खान दर्शकों के हर वर्ग में अपना फैन बेस ढूंढने में कामयाब रही हैं। चाहे वह बिग बॉस, झलक दिखला जा, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी जैसे टीवी रियलिटी शो के नियमित अनुयायी हों, या छोकरा जवान, झल्लाह वाला गाने में अपनी सनसनीखेज स्क्रीन उपस्थिति महसूस करना हों। फिल्म इश्कजादे का हिस्सा, या रणबीर कपूर और विद्या बालन जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, बेगम जान और हाल ही में वेब श्रृंखला तांडव और उनकी नवीनतम फिल्मों में स्क्रीन स्पेस साझा करना फिल्म 14 फेरे - गौहर ने यह सब किया है। भले ही वह यादातर सोशल मीडिया पर अपने सामाजिक और निजी जीवन के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन अभिनेत्री का कहना है कि समय के साथ, परियोजनाओं, विशेष रूप से फिल्मों को चुनने के उनके मानदंड बदल गए हैं, क्योंकि वह अब अपने अभिनय कौशल का पता लगाने की तलाश में हैं। गौहर ने बताया कि ईमानदारी से कहूं तो मैं किसी भी चीज को अफसोस की नजर से नहीं देखती। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मुझे बॉलीवुड फिल्म में रणबीर कपूर के साथ महिला नायक की भूमिका क्यों नहीं मिली या निर्देशक, निर्माता मुझे मुख्य भूमिकाओं के लिए क्यों नहीं मांग रहे हैं आदि। फिल्मों के लिए, फुटेज मेरे लिए मायने नहीं रखता है, चरित्र मायने रखता है। अगर आप इश्कजादे, बेगम जान में मेरे चरित्र को देखते हैं, तो कहानी में वे दृश्य और क्षण महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि हॉटस्टार का विशेष सिटकॉम शो द ऑफिस वेब स्पेस मेरे लिए दिलचस्प है और मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म से अछे शो ऑफर मिल रहे हैं। तांडव मेरे लिए एक महत्वपूर्ण शो था जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ था। मेरे पास ओटीटी के लिए कुछ चीजें हैं और सभी बहुत बहुमुखी और दिलचस्प हैं। अब एक परियोजना चुनने का मेरा पैरामीटर निर्देशकों और कहानीकारों के साथ सहयोग करना है जो एक अभिनेत्री के रूप में मेरी क्षमता का उपयोग करेंगे। मैं नई और रोमांचक भूमिकाओं के साथ चुनौती देना चाहती हूं।

क्या बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनेंगी अक्षरा सिंह?

टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का आगाज जल्द होने वाला है। इस बार यह शो टीवी से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगा, जिसे बिग बॉस ओटीटी नाम दिया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस शो को करण जौहर होस्ट करते नजर आएंगे। हर दिन से जुड़ी नई-नई खबरें सामने आ रही हैं। इस शो में हिस्सा लेने के लिए कई कंटेस्टेंट के नाम सामने आ रहे हैं। खबरें है कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनने वाली हैं। शो में अक्षरा के अलावा कई टीवी, फिल्म और म्यूजिक की दुनिया के सितारे नजर आएंगे। वही शो में हिस्सा लेने की खबरों पर अक्षरा सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है। खबरों के अनुसार अक्षरा ने बताया कि शो में उनका जाना तय नहीं हुआ है। बता दें कि अक्षरा से पहले कई भोजपुरी सितारें बिग बॉस में नजर आ चुके हैं। इनमें मोनालिसा, रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारीलाल यादव, और दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे नाम शामिल है। सिंगर नेहा भसीन बिग बॉस ओटीटी की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट बन चुकी हैं। वूट सिलेक्ट ने नेहा का इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। शो के पहले 6 हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर दिखाए जाएंगे। ओटीटी पर बिग बॉस को करण जौहर होस्ट करेंगे।

कोंकणा सेन शर्मा की बढ़ती उम्र को देखकर यूजर ने जताया अफसोस

बॉलीवुड अदाकारा कोंकणा सेन अपनी शानदार एक्टिंग के लिए फेमस हैं। अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत कोंकणा दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं। एक्टिंग के अलावा कोंकणा बॉलीवुड में अपनी बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। इन्हीं सब के बीच कोंकणा ने उम्र को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर को बड़े ही प्यार से फटकार लगाई हैं, जिसकी वह से वह खबरों में हैं। दरअसल, कोंकणा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी अपनी डॉग के साथ कुछ खास तस्वीरों को शेयर किया है। इस फोटो को शेयर करते हुए कोंकणा ने कैप्शन में बताया है कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी लविंग पेपिता (डॉग का नाम) को बड़ी सावधानी और केयर के साथ बचाया है। यह डॉग उनका पहला पालतू है, जिसको उन्होंने कुछ खास ट्रेनिंग के बाद एक्सपर्ट बना दिया है।

भारत की अदिति अशोक ने गोल्फ में जगाई पदक की उम्मीद

टोक्यो ओलंपिक: गोल्फ में पदक जीतकर रच सकती हैं इतिहास

टोक्यो। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक की महिला गोल्फ प्रतियोगिता में शुक्रवार को तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वह शीर्ष पर मौजूद अमेरिका की नेल्ली कोर्डा से मात्र तीन शॉट पीछे हैं।

अदिति नेली के 3 स्ट्रोक की बढ़त को खत्म कर जीत सकती हैं स्वर्ण

अदिति से पदक की उम्मीद बनी हुई है अदिति ने तीसरे राउंड में तीन अंडर 68 का कार्ड खेला और उनका तीन राउंड का कुल स्कोर 12 अंडर 201 हो चुका है जबकि पहले नंबर पर मौजूद अमेरिकी गोल्फर कोर्डा (69) तीन राउंड के बाद 15 अंडर 198 के स्कोर के साथ गोल्ड जीतने की दावेदार बनी हुई हैं। शनिवार को फाइनल राउंड खेला जाएगा। फिलहाल अमेरिका की कोरडा नेली पहले नंबर पर हैं। अगर अदिति नेली के 3 स्ट्रोक की बढ़त को खत्म करने में सफल हो जाती हैं तो फिर वह स्वर्ण पदक भी जीत सकती हैं। ओलंपिक में गोल्फ सिर्फ चौथी बार खेला जा रहा है। अगर खराब मौसम के कारण शनिवार को फाइनल राउंड नहीं होता है तो अदिति रजत पदक अपने जीत लेंगी। वहीं अगर फाइनल राउंड पूरा होता है तो वह वह स्वर्ण पदक अपने नाम कर सकती हैं। अदिति अगर पदक जीतती हैं तो वे गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी होंगी। अदिति ने तीसरे राउंड में पांच बर्डी खेली और दो बोगी मारी। अदिति ने पहले दो राउंड में 67 और 66 के कार्ड खेले थे। उन्हें अपने इस प्रदर्शन को एक और राउंड में बरकरार रखने की जरूरत है और वह नया इतिहास बना सकती हैं। अदिति संयुक्त तीसरे स्थान पर मौजूद चार खिलाड़ियों से दो शॉट आगे हैं। महिला गोल्फ में एक अन्य भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर (72) तीन राउंड के बाद सात ओवर 220 के स्कोर के साथ संयुक्त 51वें स्थान पर हैं।

हार के बाद भी भारतीय महिला टीम ने जीता दिल

ब्रिटेन की टीम 4 -3 से जीती, भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में बजाईं तालियां

टोक्यो। अपने जुझारूपन और दिलेरी से इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला ओलंपिक पदक जीतने का सपना टूट गया जब ब्रिटेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के रोमांचक मुकाबले में उसे 4 -3 से हरा दिया। लेकिन भारतीय महिला टीम में ओलंपिक में जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना जज्बा दिखाया। इस जज्बे ने सभी भारतवाशियों का दिल जीत लिया। ग्रेट ब्रिटेन की खिलाड़ी मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती नजर आईं। वे भी जानती थीं कि उन्हें इस जीत के लिए भारतीय टीम ने कड़ी मेहनत करवाई है। ब्रिटेन की टीम ने भारतीय खिलाड़ियों को सम्मान भी दिया। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं। मुकाबला कहीं से भी एकतरफा नहीं था और अगर कुछ मूव्स सही बन गए होते तो तस्वीर उलट भी सकती थी।

फाइनल में पहुंचकर पहले ही सफलता के नए मानदंडों को छू लिया थ । कांस्य पदक जीतने के करीब भी पहुंची लेकिन रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता दुनिया की चौथे नंबर की ब्रिटिश टीम ने उसके साथ करोड़ों भारतीयों का भी दिल तोड़ दिया। भारतीय टीम ने पांच मिनट के भीतर तीन गोल किए। गुरजीत कौर ने 25वें और 26वें मिनट में जबकि वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में गोल दागे। ब्रिटेन के लिए एलेना रायेर ने 16वें, साारा रॉबर्टसन ने 24वें, कप्तान होली पीयर्न वेब ने 35वें और ग्रेस बाल्डसन ने 48वें मिनट में गोल दागे। भारतीय महिला टीम ने भी दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए हाफटाइम तक 3-2 की बढत बना ली। ब्रिटेन ने हालांकि दूसरे हाफ में जबर्दस्त आक्रामक खेल दिखाते हुए दो गोल करके भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तीसरे क्वार्टर में 35वें मिनट में कप्तान पीयरने-वेब होली ने शानदार गोल कर ग्रेट ब्रिटेन को 3-3 से बराबरी पर ला कर खड़ा कर दिया। फिर 47वें मिनट तक मैच बराबरी पर रहा, लेकिन डिफेंडर बाल्सडन ग्रेस ने 48वें मिनट में गोल करके ग्रेट ब्रिटेन को 4-3 से बढ़त दिला दी। इसके बाद बचे मैच के आखिरी 12 मिनटों में भारतीय खिलाड़ियों ने एक गोल की तलाश में काफी मशक्कत की, लेकिन उनकी कोशिशें सफल नहीं हुईं और ग्रेट ब्रिटेन ने मैच को 4-3 से जीत लिया। भारत का इससे पहले ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1980 में था जब महिला टीम चौथे स्थान पर रही थी। उस समय सेमीफाइनल नहीं होते थे और छह टीमों ने राउंड रॉबिन आधार पर खेला था जिनमें से दो फाइनल में पहुंची थी ।

ब्रिटेन की गोलकीपर मैडेलिन क्लेयर भारत की नेहा गोयल को सांत्वना देते हुए।

भारतीय महिला हॉकी टीम को ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल मैच में ब्रिटेन से हार मिली। लेकिन टीम के खेल की खूब तारीफ हो रही है। भारतीय टीम ने गत चैंपियन के लिए मुकाबला आसान नहीं होने दिया। ओलंपिक से पहले भारतीय टीम से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद बहुत कम होगी लेकिन टूर्नामेंट में खत्म होने के बाद इस टीम ने करोड़ो दिल जीत लिए। और इसमें ब्रिटेन भी शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन हॉकी ने ट्वीट किया, क्या मुकाबला था। क्या शानदार विरोधी टीम थी। भारतीय हॉकी टीम तुमने टोक्यो ओलंपिक में कमाल का खेल दिखाया है। तुम्हारा आने वाला वक्त कमाल के होने वाला है। वाकई, इससे पता चलता है कि भारतीय महिला टीम ने कितना शानदार प्रदर्शन किया कि विपक्षी टीम को भी तारीफ करनी पड़ी। टीम अहम मौके पर चूक गई। लेकिन टीम के प्रदर्शन ने ब्रिटेन को भी प्रभावित किया।

भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच शोर्ड मारिन का इस्तीफा

भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक का प्लेऑफ मुकाबला इस टीम के साथ उनकी आखिरी जिम्मेदारी थी। इस 47 वर्षीय कोच की देखरेख में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के चौथे स्थान पर रहने का श्रेय उनके प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। नीदरलैंड के इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा, मेरी कोई योजना नहीं है क्योंकि भारतीय महिलाओं के साथ यह मेरा आखिरी मैच था। यह अब जानेका (शोपमैन) के हवाले है।

हॉलैंड ने जीता महिला हॉकी का गोल्ड: हॉलैंड ने अर्जेंटीना को को 3-1 से हराकर टोक्यो ओलम्पिक में महिला हॉकी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है।

हमें भारतीय महिला हॉकी टीम पर गर्व: खेल मंत्री

भारतीय महिला हॉकी टीम के जज्बे की तारीफ करते हुए खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें टीम पर गर्व है। उन्होंने लिखा, भारत की बेटियां। हमारी समर्पित खिलाड़ी। हमें आप पर गर्व है। उन्होंने लिखा, हमारी महिला हॉकी टीम ने जबर्दस्त जुझारूपन दिखाया । इससे हमें आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। आपने रास्ता दिखा दिया है । पूर्व खेलमंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि हॉकी का स्वर्णिम युग लौट आया है।उन्होंने कहा, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपने अंतिम चार में पहुंचकर शानदार प्रदर्शन किया। आपने भारत को गौरवान्वित किया है। पुरूष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और पूर्व हॉकी खिलाड़ी वीरेन रासकिन्हा ने कहा कि ओलंपिक में महिला टीम का सफर इन खेलों की सर्वश्रेष्ठ गाथाओं में से है। मनप्रीत ने ट्वीट किया, यह हमारी महिला टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किस्मत ने साथ नहीं दिया लेकिन वे आखिर तक लड़ी। उन्होंने देश का दिल जीता और हमें उन पर गर्व है। चैम्पियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बधाई टीम इंडिया। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले और वी वी एस लक्ष्मण ने कहा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन आने वाली पीढ़ी के लिये प्रेरणास्रोत बनेगा ।

कांस्य पदक मुकाबले में हारे दीपक, उनके कोच भी ओलंपिक से बाहर

दीपक पुनिया कांस्य पदक मुकाबले में सैन मैरिनो के नाजेम मायलेस एमिने से 4-2 से हारे गए। 6 मिनट के इस मुकाबले में दीपक 5 मिनट 40 सेकंड तक 2-1 से आगे थे, लेकिन इसके बाद नाजेम ने सिंगल लेग अटैक के जरिए दो पॉइंट जुटाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया। भारतीय दल ने फैसले के खिलाफ अपील की जो उनके खिलाफ गई। इससे विरोधी पहलवान को 1 पॉइंट और मिल गया और उसने बाउट 4-2 से जीत ली। रेसलर दीपक पुनिया के विदेशी कोच मोराड गेड्रोव को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। गेड्रोव पर आरोप है कि ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में दीपक की हार के बाद वे रेफरी रूम में गए और मुकाबले में निर्णय करने वाले रेफरी पर हमला कर दिया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने तुरंत इस मामले की शिकायत इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी से की है। इस मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है।

ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे हरियाणा के खिलाड़ी भी होंगे मालामाल

रोहतक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर भी रहे राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जायेगी। राज्य की खेल नीति में हालांकि ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में भाग लेना अपने आप में गर्व की बात है। राज्य की खेल नीति के अनुसार इन खेलों में किसी कारणवश पदक न लाने वाले खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके अनुसार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जिनमें से प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपये की राशि खेलों के शुरू होने से पूर्व दी जा चुकी है तथा शेष 10-10 लाख रुपये की राशि खिलाड़ियों के ओलंपिक सम्पन्न होने के बाद वापिस लौटने पर दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल नीति में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को छह करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए चार करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपये देने का ही प्रावधान है। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलम्पिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस टीम में प्रदेश के दो खिलाड़ी शामिल हैं जिन पर सभी को गर्व है। इसी तरह महिला हॉकी टीम ने भी बहादुरी के साथ कांस्य पदक के लिए मैच खेला। इस टीम में प्रदेश के नौ खिलाड़ी हैं। सरकार इन्हें भी 50-50 लाख रुपए की राशि देगी।

संक्षिप्त खबर

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया से पहली बार जीती टी 20 सीरीज

ढाका। कप्तान महमुदुल्लाह (52) के शानदार अर्धशतक और गेंदबाजों के सटीक प्रदर्शन से बांग्देश ने मुश्किल पिच पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी 20 मुकाबले में शुक्रवार को 10 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त बना ली। बांग्लादेश ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 127 रन का मामूली स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में चार विकेट पर 117 रन पर रोककर जीत अपने नाम की। यह पहली बार है जब बंगलादेश ने किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीन मैचों में जीत हासिल की है। बांग्लादेश की पारी में कप्तान महमुदुल्लाह ने 53 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 52 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल मार्श ने 47 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाए जबकि एलेक्स कैरी ने नाबाद 20 रन बनाए लेकिन वह टीम को जीत की मंजिल पर नहीं ले जा सके। महमुदुल्लाह को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

पोलैंड के तोमाला ने 50 किमी पैदलचाल में स्वर्ण जीता

टोक्यो। पोलैंड के डेविड तोमाला ने ओलंपिक में 50 किलोमीटर पैदलचाल का स्वर्ण पदक जीत लिया है ।यह इस स्पर्धा का आखिरी पदक है। तोमाला ने तीन घंटे 50 मिनट और आठ सेकंड में दूसरी तय की। जर्मनी के जोनाथन हिलबर्ट दूसरे स्थान पर रहे जिन्होंने उनसे 36 सेकंड अधिक का समय लिया। पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक में 50 किलोमीटर पैदल चाल नहीं होगी और शायद यह ओलंपिक में कभी ना लौटे। इसे 1932 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था और 1976 को छोड़कर हर बार इसका आयोजन किया गया है।

एमएस धोनी को वापस मिला उनका ब्लू टिक

नई दिल्ली। ट्विटर ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि कुछ ही देर बाद उनका अकाउंट वापस वेरिफाई कर दिया गया। अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर बीते कुछ माह से लगातार विवादों में फंसा हुआ है। माही का वेरिफिकेशन बैज क्यों हटाया गया, कैसे वापस आया इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दिग्गज पूर्व क्रिकेटर ने आखिरी ट्वीट आठ जनवरी को ट्वीट किया था। इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर महेंद्र सिंह के करीब 8.2 मिलियन फॉलोअर हैं। हो सकता है कि अपनी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए ट्विटर ने यह कार्रवाई की हो।

डेविस कप के लिए पांच सदस्यीय भारतीय टीम घोषित

नई दिल्ली। फिनलैंड के खिलाफ 17 और 18 सितम्बर को होने वाले डेविस कप विश्व ग्रुप एक मुकाबले के लिए पांच सदस्यीय भारतीय डेविस कप टीम की घोषणा कर दी गयी। टीम के सदस्यों में प्रजनेश गुणेश्वरन , सुमित [illegible]

भारतीय पैदल चाल खिलाड़ियों का अभियान समाप्त

गुरप्रीत, प्रियंका और भावना ने किया निराश

टोक्यो। भारत की राष्ट्रीय रिकार्डधारी प्रियंका गोस्वामी शुक्रवार को यहां ओलंपिक की महिलाओं की 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में आधी दूरी तक अच्छी स्थिति में थीं लेकिन अंत में 17वें स्थान पर जबकि हमवतन भावना जाट 32वें स्थान पर रहीं। गुरप्रीत सिंह पुरूषों की 50 किलोमीटर पैदल चाल पूरी नहीं कर सके और गर्मी तथा उमस के कारण ऐंठन की वजह से नाम वापस ले लिया। वह 35 किमी की दूरी दो घंटे 55 मिनट 19 सेकंड में पूरी करके 51वें स्थान पर थे। इसके बाद वह अलग बैठ गए और मेडिकल टीम ने उनकी मदद की । इससे भारतीय पैदल चाल खिलाड़ियों का अभियान निराशाजनक तरीके से समाप्त हुआ। पच्चीस वर्षीय प्रियंका ने एक घंटे 32 मिनट 36 सेकेंड का समय निकाला जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ एक घंटे 28 मिनट और 45 सेकेंड के प्रदर्शन से बाहर था जबकि यह उन्होंने फरवरी में नेशनल ओपन पैदल चाल चैम्पियनशिप के दौरान ही बनाया था। स्पर्धा हालांकि काफी गर्मी और उमस भरी परिस्थितियों में संपन्न हुई। प्रियंका शुरू में आगे चल रहे खिलाड़ियों में शामिल थी बल्कि आठ किलोमीटर तक दूरी तय करने के बाद वह सबसे आगे थीं लेकिन धीरे धीरे वह खिसकती चली गयीं। भावना आगे चल रही खिलाड़ियों के साथ अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख सकीं और शुरू से ही पीछे चल रही थीं जिससे वह एक घंटे 37 मिनट 38 सेकेंड से 32वें स्थान पर रहीं।

नया एशियाई रिकॉर्ड बनाने के बावजूद फाइनल में नहीं पहुंच सकी भारतीय रिले टीम

भारत की चार गुना 400 मीटर रिले टीम शुक्रवार को नया एशियाई रिकॉर्ड बनाने के बावजूद इस स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई। मोहम्मद अनस, निर्मल नोह टॉम , अरोकिया राजीव, और अमोज जैकब की भारतीय चौकड़ी ने चार गुना 400 मीटर रिले की दूसरी हीट में तीन मिनट 0025 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में चौथे तथा ओवरआल नौंवें स्थान पर रहे। वह फाइनल में जगह बनाने से मामूली एक स्थान के अंतर से चूक गए। दोनों हीट से शीर्ष तीन -तीन टीमों और उसके बाद दो सर्वश्रेष्ठ टीमों को जगह मिलती है।

सेमीफाइनल में हारे बजरंग पुनिया

कांस्य के लिए लड़ेंगे आज

टोक्यो। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्वर्ण पदक की उम्मीद पहलवान बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबले में ओंलपिक के कांस्य पदक विजेता और तीन बार के विश्व चैंपियन अजरबैजान के हाजी एलियेव से 5-12 से हार गए। बजरंग अब कांस्य पदक के लिए रेपेचेज मुकाबले के विजेता से खेलेंगे। एक ही दिन में तीन कुश्ती लड़ना आसान नहीं है। दो कुश्ती लगातार जीतने के बाद बजरंग पुनिया सेमीफाइनल का महत्वपूर्ण मुकाबला अजरबैजान के पहलवान से हार गए। इसमें भी कोई शक नहीं कि अजरबैजान के अलीयेव हाजी बहुत अच्छी कुश्ती लड़े। शुरुआत धीमी करने के बाद वो फिर एकदम से बजरंग पुनिया पर भारी पड़ गए और फिर उन्हें उभरने नहीं दिया। जो फीतले दाँव बजरंग की पहचान रहा है उसी दाँव को अलीयेव ने बजरंग के खिलाफ कुश्ती के अहम पड़ाव पर लगाकर लगातार 4 पॉइंट जीत लिए। बजरंग पहलवान 5-12 से हार गए। तीनों कुश्तियाँ एक दिन में ना होकर बजरंग को अलगे दिन खेलने का मौका मिलता तो शाद परिणाम बेहतर हो सकते थे। सेमीफाइनल मुकाबले में अजरबैजान के पहलवान अलीयेव शुरुआत से ही बजरंग पर भारी पड़े। बजरंग पहले ही पीरिएड में अपने प्रतिद्वंदी से 4-1 से पिछड़ गए। दूसरे पीरिएड में अलीयेव ने बजरंग पुनिया का मशहूर फीतले दांव उन्हीं पर लगा दिया और अंक हासिल कर लिए। दूसरे पीरिएड में बजरंग 7-1 से पीछे हो गए। इसे बाद उन्होंने 2 अंक बटोरे। लेकिन अलीयेव ने भी इस दौरान 2 अंक बटोर कर बजरंग की वापसी की उम्मीद धूमिल कर दी। आखिरी पलों में बजरंग ने फिर 2 अंक लिए। लेकिन हाजी भी 2 अंक बटोरने में सफल रहे। इस दौरान बजरंग 5-11 से पीछे हो गए। वहीं अंतिम पलों में बजरंग के कोच ने हाजी के दांव को चुनौती लेकिन उसे मान्य नहीं किया या।

पुनिया ने दिखाई खेल भावना

बजरंग पुनिया ने ईरान के मुर्तजा चेका घियासी के खिलाफ जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। बजरंग को जब जीत मिली तो ईरान के पहलवान मुर्तजा निराश होकर मैट पर ही लेटे हुए थे। ऐसे में बजरंग ने खेल भावना का परिचय दिया और उन्हें उठने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बजरंग के इस खेल भावना की चर्चा हर तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर उनकी यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है।

सीमा का सफर समाप्त

ट्यूनीशिया की सारा हामदी के महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती के 50 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तीन बार की ओलंपिक पदक विजेता अजरबैजान की मारिया स्टैडनिक से हारने के साथ ही भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला का टोक्यो ओलंपिक अभियान खत्म हो गया।

कोहली को पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दी सलाह

नई दिल्ली। भारतीय कप्तान विरा कोहली ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहल पारी में गोल्डन डक (शून्य) अपना विकेट गंवा दिया। बल्लेबाजी के लिए आए और जेम्स एंडरसन के खिलाफ अपनी पारी पहली ही गेंद पर विकेट के पीछे जो बटलर को कैच थमा बैठे। विरा कोहली भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान नौवीं ब शून्य पर आउट होने वाले पह खिलाड़ी भी बने। अब ओपनर टेस्ट मैच में विराट कोहली की खरा बल्लेबाजी के बाद पाकिस्तान क्रिके टीम के पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा विराट कोहली को सलाह दे डाली उन्होंने कहा कि, विराट कोहली केएल राहुल से सीखना चाहिए कैसे इंग्लैंड में सॉफ्ट हैंड से खेल जाता है। रमीज राजा ने अपने यूट्यू चैनल पर बात करते हुए कहा वि महान खिलाड़ी भी अपने खेल सुधार करने के लिए युवा बल्लेबाजों सीख सकते हैं। उन्होंने चैट के दौरा विराट कोहली और केएल राहुल बल्लेबाजी (पारी) की तुलना करते हु कहा कि, जब के एल राहुल बैटि कर रहे थे तो सब कुछ गेम में अच्छ चल रहा था। वो गेंद के काफी करी जाकर खेल रहे थे और उन्हें पता कि उनका ऑफ स्टंप कहां पर है। इ तरह की परिस्थितियों में इसी तरह बैटिंग की जाती है।

टीम इंडिया को पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त

केएल राहुल ने खेली 84 रन की पारी, पुछल्ले बल्लेबाजों का भी शानदार प्रदर्शन

नार्टिंघम। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट मैच के तीसरे दिन केएल राहुल के84 रन और पुछल्ले बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की दम पर पहली पारी में 278 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों ने टीम को पहली पारी में 95 रन की महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी।

एंडरसन ने भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराकर कुंबले से आगे निकल गए। भारत के आखिरी तीन विकेटों की साझेदारी में 73 रन बने। ऑल राउंडर रवींद्र जडेजा के 56, मोहम्मद शमी के 13 और जसप्रीत बुमराह के 28 रनों का योगदान दिया। तीसरे सेशन में बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा है। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना [illegible] चार विकेट पर 125 रन से आगे खेलना शुरू किया था। नाबाद बल्लेबाज ऋषभ पंत सात रन से आगे खेलते हुए तेज गेंदबाज ओली [illegible] रन बनाए। राहुल और जडेजा ने छठे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। एंडरसन ने राहुल को आउट कर न केवल इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ा बल्कि कुंबले से भी आगे निकल गए। एंडरसन ने शार्दुल ठाकुर को शून्य पर आउट कर अपना 621 वां विकेट लिया। जडेजा और शमी ने आठवें विकेट के लिए 27 रन जोड़े। जडेजा को रॉबिंसन ने स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथों कैच कराया। जडेजा ने 86 गेंदों पर 56 रन में आठ चौके और एक छक्का लगाया। बुमराह ने 34 गेंदों पर 28 रन में तीन चौके और एक छक्का लगाया। बुमराह ने मोहम्मद सिराज के साथ आखिरी विकेट के लिए 33 रन जोड़े। सिराज सात रन पर नाबाद रहे। इंग्लैंड की तरफ से [illegible]

एंडरसन ने कुंबले को पीछे छोड़ा

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन शुक्रवार को भारत के दिग्गज अनिल कुंबले के 619 विकेटों को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर काबिज हो गए। एंडरसन ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन केएल राहुल (84) को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराकर यह उपलब्धि हासिल की। अब उनसे अधिक विकेट श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन (800) और आस्ट्रेलिया के शेन वार्न (708) के नाम पर दर्ज हैं। एंडरसन ने 2003 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और वह अपना 163वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वह सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने

पूर्व चयनकर्ता ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारतीय टीम, इन खिलाड़ियों को किया शामिल

नई दिल्ली । नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। इसी लंबी सीरीज के लिए टीम इंडिया इस समय यूके में है। इस सीरीज से ठीक पहले, शिखर धवन की कप्तानी में दूसरे दर्जे की भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेली थी, जिसमें वनडे सीरीज भारत 2-1 से जीता था, लेकिन 1-2 से टी20 सीरीज गंवाई थी।झ

इस सीरीज परिणाम से अधिक ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप 2021 के लिए एक संतुलित टीम खोजने के लिए नए खिलाड़ियों को आजमाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें कुछ खिलाड़ी सफल हुए तो कुछ को निराशा हाथ लगी। हालांकि, अब भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता रहे एमएसके प्रसाद ने टी20 विश्व कप के

एमएसके प्रसाद ने कहा कि शिख धवन को रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में हो चाहिए। उन्होंने कप्तान विराट कोहली नई बल्लेबाजी सनसनी सूर्यकुमार याद केएल राहुल और रिषभ पंत मध्यक्रम के खिलाड़ियों के रूप में चु है। प्रसाद ने समझाया कि मेगा इवे एशियाई परिस्थितियों में खेली जाएग इसलिए राहुल को टीम में होना चाहि और मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर चाहिए। पूर्व चयनकर्ता ने ये भी कहा कि आर अश्विन को भी चुना जा सक है, लेकिन उनको आइपीएल में अच्छ प्रदर्शन करना होगा।

पूर्व क्रिकेटर एमएसके प्रसाद ने ए स्पोर्ट्स वेबसाइट से बात करते हु कहा, मुझे अब भी लगता है कि शिख धवन को वहां होना चाहिए। यह ती सलामी बल्लेबाज के रूप में शिख धवन, रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ हो